आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्त सुविधा (रिटायरमेन्ट बैनीफिट) विनियम 1962, जो आवश्यक संशोधनों सहित 13 नवम्बर, 1999 के सरकारी बजट में प्रकाशित हुये थे, में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 548 (1)(ब) के अन्तर्गत निम्न संशोधन अन्य विनियमों के यथावत् रहते हुए प्रस्तावित किये जाते है:--

वर्तमान विनियम--

6(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो पेंशन योग्य दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने पर अथवा सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने की दशा में विधवा पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो या उसके न होने पर नाबालिग बच्चों को 25 वर्ष की आयु/जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक अथवा पुत्री के मामलों में विवाह होने अथवा जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने तक तथा विधवा पत्नी को आजीवन पारिवारिक पेंशन देय होगी। जो पुनर्विवाह करने पर समाप्त हो जायेगी।

प्रस्तावित संशोधित विनियम--

6-(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो पेंशन योग्य दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होगें उन्हें सेवा निवृत्त पेंशन देय होगी अथवा जो कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने की दशा में अथवा एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण हो जाने के बाद सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में, विधवा पत्नी/पति जैसी स्थिति हो या उसके न होने पर नाबालिग बच्चों को पच्चीस वर्ष की आयु/जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने, जो भी पहले हो तक अथवा पुत्री के मामलों में विवाह होने पर अथवा जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने तक तथा विधवा पत्नी अथवा पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन देय होगी जो पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो के पुनर्विवाह करने पर समाप्त हो जावेगी।

उपरोक्त संशोधन पूर्व में किए गए संशोधनों की तिथि 01--11--95 से प्रभावी समझे जावेगें।

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण शासनादेश

संख्या---सा-3-828/दस-924-88

प्रेषक,

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 25 जून, 1984

विषय --नई पारिवारिक पेन्शन स्कीम 1965 के अधीन एक वर्ष की अविरल सेवा सम्बन्धी प्राविधान.....शिथिलीकरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917-61, दिनांक 24 अगस्त 1966 के प्रस्तर-3 (क) के अधीन पारिवारिक पेंशन की अनुपन्यता के लिए सेवारत अवस्था में मृत्यु होने की दशा में एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करना आवश्यक था। शासनादेश संख्या सा-3-1358/दस-918-79, दिनांक 21 सितम्बर, 1979 में उक्त प्राविधान को इस शर्त के अधीन समाप्त कर दिया गया है कि यदि सरकारी सेवक ने सेवा में प्रवेश करते समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, तो उस दशा में यदि उनकी सेवा अवधि एक वर्ष से कम है, तो भी यह परिवार पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा। शासन के सम्मुख दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के पूर्व के कुछ इस प्रकार के मामले भी संदर्भित हुये हैं जिनमें सरकारी सेवक की मृत्यु एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करने के पूर्व हो गयी है। उदाहरणतया एक अस्थायी सेवक ने किसी विभाग में सेवा की और छटनी के आधार पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई। कालान्तर में उन्हें पुनः इसी शासन के अधीन किसी सरकारी पद पर नियुक्त कर लिया गया। दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के पूर्व की व्याख्या के अनुसार उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन अनुपन्य नहीं होगा। ऐसे मामलों में शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार को पारिवारिक पेंशन अनुपन्य कराये जाने के प्रयोजन के लिए सेवा की दो अवधियों के बीच उत्पन्न व्यवधान को सतत मान लिया जाये। उक्त बिन्दु

7

आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) विनियम 1962, जो आवश्यक संशोधनों सहित 30 मार्च 1995 के सरकारी गजट में प्रकाशित हुई थीं, में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 548)1(च) के अन्तर्गत निम्न संशोधन) अन्य विनियमों के यथावत रहते हुए प्रस्तावित किये जाते हैं -

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित संशोधन
1(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) 1962 कहा जायेगा ।	1(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्त सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) विनियम 1962 होगा। 2(2) द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि उन विनियमों में औसत परिलब्धियों की वह ही उपयुक्त परिभाषा मान्य होगी जिसे समय-समय पर राज्य सरकार अपने पेंशनरों के लिए परिभाषित करे ।
4(2) डेथकम (रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) मृत्यु एवं सेवा निवृत्त उपादान यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को, जिन्होने उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या-5 के उपविनियम । से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपादान दिया जायेगा (दस वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपादान सर्विसग्रेच्युटी देय होगी) उसकीदर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी । मृत्यु उपादान सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार की मृत्यु उपादान अनुमन्य होगा, जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों कादो गुना एक से अधिक किन्तु पाँच वर्ष सेकम की सेवा पर परिलब्धियोंका छः गुना, पाँच से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के अधिक के बराबर बराबर जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (तेंतीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि ढाई लाख रूपये से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा ।	4(2) मृत्यु एवं सेवा निवृत्त उपादान (डेथकम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी । यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को जिन्होने उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या-5 के उपविनियम । से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपादान दिया जायेगा (दस वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपादान सर्विस ग्रेच्युटी देय होगी) उसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी । मृत्यु उपादान सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को मृत्यु उपादान अनुमन्यहोगा जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का दो गुना एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का छः गुना, पाँच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष अथवा उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (तेंतीस) गुने के बराबर होगी किन्तु देय धनराशि ढाई लाख समय से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा ।

क्रमशः.....2.

आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) विनियम 1962, जो आवश्यक संशोधनों सहित 30 मार्च 1995 के सरकारी गजट में प्रकाशित हुई थीं, में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 548 (1)(च) के अन्तर्गत निम्न संशोधन) अन्य विनियमों के यथावत रहते हुए (प्रस्तावित किये जाते हैं :-

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित संशोधन
1(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) 1962 कहा जायेगा ।	1(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्त सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) विनियम 1962 होगा ।
--	2(2) द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि उन विनियमों में ओसत परिलब्धियों की वह ही उपयुक्त परिभाषा मान्य होगी जिसे समय समय पर राज्य सरकार अपने पेसनरो के लिए परिभाषित करे ।
4(2) डेथकम (रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) मृत्यु एवं सेवा निवृत्त उपादान –	4(2) मृत्यु एवं सेवा निवृत्त उपादान (डेथकम – रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी ।
यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को, जिन्होने उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या–5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपादान दिया जायेगा (दस वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपादान सर्विस ग्रेच्युटी देय होगी (उसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिये आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी, मृत्यु उपादान सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार की मृत्यु उपादान अनुमन्य होगा, जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का दो गुना एक से अधिक किन्तु पॉच वर्ष से कम की सेवा पर परिलब्धियों का छः गुना, पॉच से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के अधिक के बराबर बराबर जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (तेतीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि ढाई लाख रूपये से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उप विनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा ।	यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुये व्यक्ति/ व्यक्तियों को जिन्होने उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या–5 के उप विनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपादान दिया जायेगा (दस वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपादान सर्विस ग्रेच्युटी देय होगी (उसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिये आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी । मृत्यु उपादान सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को मृत्यु उपादान अनुमन्य होगा, जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का दो गुना एक वर्ष, अथवा उससे अधिक किन्तु पॉच वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का छः गुना, पॉच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु बीस वर्ष में कम सेवा पर परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष अथवा उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (तेतीस) गुने के बराबर होगी किन्तु देय धन राशि ढाई लाख समय से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

नगर निगम

प्रस्तावित नम्र संशोधन

द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं ये संशोधन नगर निगम का 12 मई 1995 के अनुसार उपनियम विनियमावली 548(अ) के अन्तर्गत शासकीय गजट में प्रकाशित कीजाने के पश्चात संशोधित की जायेगी नवम्बर 1995 से प्रभावी होंगे।

नगर निगम	प्रस्तावित संशोधन
1§ इन विनियमों का नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा §रिटायरमेन्ट बेनीफिट§ विनियम 1962 कहा जायेगा।	1§ इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा §रिटायरमेन्ट बेनीफिट§ 1962 कहा जायेगा।
2§1§ अधिनियम§एक्ट§ से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 §एक्ट 2-1959§	2§1§ अधिनियम को अब उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 §यूपी अधिनियम 2 सन् 1959§ कहा जायेगा।
2§9§ स्पष्टीकरण:- विनियम 2§9§ में निहित स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का तात्पर्य है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा 25 वर्ष की अर्हकारी सेवापूर्ण कर लेने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी या सेवक स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि जिस तिथि से वह स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति चाहता है उसके 3 माह पूर्व से उसे तत्संबंध मुख्य नगर अधिकारी को नोटिस देना होगा तथा पूर्णतया अशक्त होजाने पर किसी अधिकारी को मु0 न0 अधिकारी द्वारा आवश्यक जाँच के पश्चात् 3 माह का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जा सकता है।	2§9§ स्पष्टीकरण:- विनियम 2§9§ में निहित स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का तात्पर्य है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी या सेवक स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि जिस तिथि से वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति चाहता है उसके 3 माह पूर्व उसे प्रार्थना पत्र/मुख्य नगर अधिकारी को नोटिस देना होगा।
3§ उपलब्धियाँ §इमोल्यूमेंट§ से तात्पर्य है:- वेतन फाइनेन्शियल § हैन्डबुक भाग-2 से 4 वाल्यूम 2 के फन्डामेंटल का 9§21§ में परिभाषित तथा समय-समय पर संशोधित परिभाषा के अनुसार तथा	3§ परिलब्धियों §इमोल्यूमेंट§ से तात्पर्य है:- §क§ परिलब्धियों से तात्पर्य अब वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग 2 से 4 खंड 2 के मूलनियम 9(21) में परिभाषित वेतन से है। तथा समय-समय पर संशोधित रूप पर परिभाषित मूल वेतन से होगा।
§ख§ मासिक भत्ता अथवा वेतन अन्य भत्ता § ग § यदि कोई हो जो अधिकारी की मृत्योपरान्त उसकी सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु जैसी भी दशा हो, के समय औ प्राय §एडी शिनल§ हो	निरस्त किया जाता है।
4§1§ मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान जिन अधिकारियों पर यह विनियम लागू होंगे उनकी सेवानिवृत्ति होने पर अंतिम रिक्त उपादान §ग्रेच्युटी§ भी दिया जायेगा, जो इनकी मासिक उपलब्धियों के 16.5 गुने से अधिक न होकर कम से कम होगा जो उनकी मासिक उपलब्धियों के 1/4 को उनके द्वारा की गई अर्हकारी सेवा के पूरे अर्द्ध वार्षिक काल की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगा।	4§1§ सेवानिवृत्ति उपादान §रिटायरमेंट ग्रेच्युटी§ सेवा निवृत्ति उपादान §रिटायरमेंट ग्रेच्युटी§ 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण हो जाने पर ही अनुमन्य होगी तथा उसकी धनराशि पूरक पूर्ण छमाही सेवा अवधि के लिए अन्तिम आहरित परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर होगी। जिसकी अधिकतम अन्तिम परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुना के बराबर होगा।

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 30 मार्च, 1996 ई० (चैत्र 10, 1918 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि

सूचना

आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेनीफिट) विनियम, 1962 में शासनादेश 1505-ए/9-7-1995-3-के (38)-75 दिनांक 22 मई, 1995 के अनुसार उपरोक्त विनियमावली, जो कि निगम अधिनियम, 1959 की धारा 548 (1) (एफ) के अन्तर्गत निर्मित एवं संशोधित की गयी है, में प्रस्तावित निम्न संशोधन अधिनियम की धारा 548 (3) के अन्तर्गत शासकीय गजट में एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। ये संशोधन 1 नवम्बर, 1995 से प्रभावी होंगे :

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
1—(1) इन विनियमों का नाम आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेनिफिट) विनियम, 1962 होगा।	1—(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनिफिट), 1962 कहा जायेगा।
2—(1) अधिनियम (अथवा ऐक्ट) से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (ऐक्ट 2, 1959)	2—(1) अधिनियम को अब उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उ० प्र० अधिनियम 2 सन् 1959) कहा जायेगा।
2—(9) स्पष्टीकरण—	2—(9) स्पष्टीकरण—
विनियम 2 (9) में निहित स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का तात्पर्य है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा 25 वर्ष की अहंकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी या सेवक स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि जिस तिथि से वह स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति चाहता है उसके 3 माह पूर्व वो उसे	विनियम 2 (9) में निहित स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का तात्पर्य है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा 20 वर्ष की अहंकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी या सेवक स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि जिस तिथि से वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति चाहता है उसके

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
तदर्थ मुख्य नगर अधिकारी को नोटिस देना होगा तथा 3 माह पूर्व उसे प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी पूर्णतया अशक्त हो जाने पर किसी अधिकारी को मु० ना० अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच के पश्चात् 3 माह का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जा सकता है।	
3--उपलब्धियां (इमोल्यूमेन्ट) से तात्पर्य है--	3--परिलब्धियों (इमोल्यूमेन्ट) से तात्पर्य
(क) वेतन फाइनेन्शियल हैन्ड बुक (भाग 2 से 4) वोल्यूम 2 के फण्डामेंटल रूल 9 (21) में परिभाषित तथा समय-समय पर संशोधित परिभाषा के अनुसार तथा,	(क) परिलब्धियों से तात्पर्य अत्र वित्तीय [illegible] भाग 2 से 4 खंड 2 के मूलनियम 9 (21) में समय-समय पर परिभाषित मूल वेतन से है। भविष्य में शासन
(ख) महंगाई भत्ता अथवा तत्समय अन्य भत्ता यदि कोई हो जो अधिकारी को प्रतिमाह उसकी सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु, जैसी भी दशा हो, के समय उसे प्राप्य (एडमिसिबिल) हो।	(ख) निरस्त किया जाता है।
4--(1) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान--जिन अधिकारियों पर यह विनियम लागू होगा उनको सेवानिवृत्त होने पर अतिरिक्त उपादान (ग्रेचुटी) भी दिया जायेगा जो इनकी मासिक उपलब्धियों के 16.5 गुने से अधिक न होकर वह धन होगा जो उनकी मासिक उपलब्धियों के 1/4 को उनके द्वारा की गई अहंकारी सेवा के पूर्ण अर्द्ध वार्षिक काल की संख्या को गुणा करने पर प्राप्त होगा।	4--(1) सेवानिवृत्ति उपादान (रिटायरमेंट ग्रेच्युटी)-- सेवा निवृत्ति उपादान (रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) 5 वर्ष अहंकारी सेवा पूर्ण हो जाने पर ही अनुमन्य होगी तथा उसकी धनराशि प्रत्येक पूर्ण छमाही सेवा अवधि के लिए अन्तिम आहरित परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर होगी, जिसका अधिकतम अन्तिम परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुना के बराबर होगा।
4--(2) डेथकम (रिटायरमेंट ग्रेचुटी) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपादान--	4--(2) डेथकम (रिटायरमेंट ग्रेचुटी) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपादान--
यदि किसी अधिकारी की सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाय तो उसके द्वारा मनोनीत किए हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को, जिन्हें उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या 5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार दिया गया हो, उपादान दिया जायेगा, जिसकी धनराशि उसके वेतन के 12 गुने से कम और 16.5 गुने से अधिक न होते हुए वह धनराशि होगी जो उसकी मासिक उपलब्धियों के 1/4 को उसके द्वारा की गई अहंकारी सेवा में पूर्ण अर्द्धवार्षिक काल की संख्या में गुणा करने पर प्राप्त हो और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा।	यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुये व्यक्ति/व्यक्तियों को, जिन्होंने उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या 5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपादान दिया जायेगा। (दस वर्ष से कम अहंकारी सेवा होने पर पेन्शन के स्थान पर सेवा उपादान/सर्विस ग्रेच्युटी देय होगी) उसकी हर प्रत्यक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी। मृत्यु उपादान की दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को मृत्यु उपादान अनुमन्य होगा, जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का दो गुना एक से अधिक, किन्तु पांच वर्ष से कम की सेवा पर परिलब्धियों का छः गुना, पांच से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष या उससे अधिक अहंकारी सेवा की प्रत्यक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के आधे के

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
	बराबर, जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (तैंतीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीति न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा ।
	16 सितम्बर सन् 1993 से सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान के प्रयोजनार्थ मूल वेतन का 20 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता महंगाई वेतन के रूप में सम्मिलित करके परिलब्धियों की गणना की जायेगी । 1-4-95 से उपादान की गणना के लिए निम्न प्रकार महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में मूल वेतन के साथ जोड़कर परिलब्धियां आंगणित की जायेगी ।
	(1) मूल वेतन प्रत्येक माह रु0 3,500 तक-वेतन का 97 प्रतिशत ।
	(2) मूल वेतन प्रत्येक माह रु0 3,500 से अधिक परन्तु रु06,000 से कम-वेतन का 73 प्रतिशत परन्तु कम से कम 3,395 रुपये ।
	(3) मूल वेतन प्रत्येक माह रु0 6,000 से अधिक-वेतन का 63 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु0 4,380 ।
4--(3) उपविनियम (1) और (2) के अन्तर्गत मिलने वाले उपादान की धनराशि किसी भी दशा में रु0 50.000 से अधिक नहीं होगी ।	4--(3) उपविनियम (1) और (2) के अन्तर्गत मिलने वाले उपादान की धनराशि किसी भी दशा में रु0 2,50,000 से अधिक नही होगी ।
6--(1) प्रत्येक अधिकारी, जो सेवा निवृत्ति वेतन योग्य 10 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवा निवृत्त होने पर अथवा सेवा में रहते हुए मृत हो जाये तो उसके परिवार को नीचे उपविनियम 2 में वर्णित धनराशि से अधिक न होते हुए पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन उसकी विधवा पत्नी को आजीवन, जब तक वह पुनर्विवाह न करे अथवा परिवार के अन्य किसी सदस्य को प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्तर्गत रहते हुए अधिक से अधिक 10 वर्ष तक दिया जायगा । यह नियम इस संशोधन के प्रभावी होने के दिनांक से समस्त पेन्शनर्स की विधवा पत्नियों पर प्रभावी माना जायगा चाहे वे किसी भी दिनांक से सेवा निवृत्त हुए हो अथवा मृत हुए हों ।	6--(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो पेन्शन योग्य दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवा निवृत्त होने पर अथवा सेवा में रहते हुए अथवा सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने की दशा में विधवा पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो, या उसके न होने पर नाबालिग बच्चों को 25 वर्ष की आयु/जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक अथवा पुत्री के मामलों में विवाह होने अथवा जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने तक तथा विधवा पत्नी को आजीवन पारिवारिक पेन्शन देय होगी जो पुनर्विवाह करने पर समाप्त हो जावेगी ।
6--(2) (क) सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की दशा में उस निवृत्ति वेतन का आधा जो सम्बन्धित अधिकारी का मृत्यु होने के अगले दिन देय होता, यदि वह उस दिन नियत सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त कर दिया जाता ।	6--(2) (क) रु0 1,500 से अनधिक मूल वेतन का 30 प्रतिशत न्यूनतम 375.00 मात्र रु0 1,500 से अधिक किन्तु रु0 3,000.00 से अनधिक मूल वेतन का बीस प्रतिशत न्यूनतम 450 रुपया प्रतिमाह देय होगी । रुपया 3,000 से अधिक मूल वेतन का 15 प्रतिशत न्यूनतम रु0 600

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
प्रतिबन्ध यह कि—	तथा
6—(2) (ख) पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन का अधिक से अधिक रु० 500.00 से अधिक न होगा तथा कम से कम रु० 375.00 से कम न होगा जो 1 जनवरी, 1986 से लागू होगा।	6—(2) (ख) अधिकतम रुपया 1250.00 होगा पारिवारिक पेन्शन की न्यूनतम धनराशि रुपया होगी।
6—(3) इस भाग के अन्तर्गत कोई पेन्शन देय न होगी :	निरस्त किया जाता है।
(क) नीचे के उपनियम (4) के खंड (ख) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की जब तक कि मुख्य नगर अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि वह व्यक्ति जिसे पेन्शन दी जाने वाली है अपने पोषण के लिए मृत अधिकारी पर आश्रित था।	निरस्त किया जाता है।
(ख) किसी अविवाहित स्त्री सदस्या को उसके विवाहित होने की दशा में।	निरस्त किया जाता है।
(ग) परिवार के किसी विधवा स्त्री सदस्या को यदि वह पुनः विवाह कर लें।	निरस्त किया जाता है।
(घ) मृत अधिकारी के किसी भाई को उसके 18 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेने पर तथा	निरस्त किया जाता है।
(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति को जो मृत अधिकारी के परिवार का सदस्य न हो।	निरस्त किया जाता है।
6—(4) उपविनियम (5) के अन्तर्गत किये नामांकन पत्र में की गई व्यवस्था को छोड़कर	निरस्त किया जाता है।
(क) उस भाग के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) निम्न प्रकार दिया जायेगा :	निरस्त किया जाता है।
(1) उत्तरजीवी ज्येष्ठ विधवा को यदि मृत पुरुष अधिकारी हो अथवा पति को मृतक महिला अधिकारी हो।	निरस्त किया जाता है।
(2) विधवा पत्नी अथवा पति, जैसी भी दशा हो, के न होने पर उत्तरजीवी ज्येष्ठ पुत्र को।	निरस्त किया जाता है।
(3) उपर्युक्त नम्बर 1 व 2 की दशा के न होने पर उत्तरजीवी ज्येष्ठ अविवाहित पुत्री को तथा	निरस्त किया जाता है।
(4) उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं के अभाव में विधवा-ज्येष्ठ पुत्री को तथा 6 (4) (ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति वेतन किसी व्यक्ति को देय न होने की दशा में वह निवृत्ति वेतन (पेन्शन) निम्न प्रकार स्वीकार की जावेगी।	निरस्त किया जाता है।
(1) पिता को	निरस्त किया जाता है।
(2) पिता के न होने पर माता को	निरस्त किया जाता है।

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
(3) पिता और माता के न होने पर उत्तर जीवी ज्येष्ठ भ्राताओं में उसको जिसकी अवस्था 18 वर्ष से कम हो ;	निरस्त किया जाता है ।
(4) इन सबके न होने पर ज्येष्ठ उत्तर जीवी अविवाहिता बहिन को तथा	निरस्त किया जाता है ।
(5) उपर्युक्त नम्बर (1) से (4) में उल्लिखित के न होने पर ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा बहिन तथा	निरस्त किया जाता है ।
(6) (1) से (5) तक वर्णित व्यक्तियों के न होने की दशा में पूर्व मृत पुत्र के बच्चों को उस क्रम में जिसमें मृत अधिकारी के बच्चों को ऊपर के खण्ड (क) के उपखण्ड (2), (3) और (4) के अन्तर्गत देय हो ।	निरस्त किया जाता है ।
टिप्पणी--ऊपर के खण्ड (क) (1) के अन्तर्गत किए गए ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा शब्दों की व्याख्या मृत अधिकारी के साथ हुए विवाह सम्बन्ध को पूर्वता-क्रम से की जायेगी न कि उत्तरजीवी विधवाओं की आयु के उल्लेख से :	निरस्त किया जाता है ।
प्रतिबन्ध यह रहेगा कि पारिवारिक सेवानिवृत्ति वेतन मृतक कर्मचारी के उस पारिवारिक सदस्य को देय होगा जो किसी सेवा में न हो अथवा जो स्वयं का सेवानिवृत्त वेतन न प्राप्त कर रहा हो ।	निरस्त किया जाता है ।
तथा	
प्रतिबन्ध यह भी रहेगा कि यदि किसी मृतक कर्मचारी का उत्तरजीवी ज्येष्ठ उत्तराधिकारी जो महापालिका अथवा किसी सरकारी सेवा में है तो उससे कनिष्ठ उत्तराधिकारी जो किसी सरकारी अथवा महापालिका की सेवा में न हो, को पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत किया जायेगा यह प्रतिबन्ध नाराकार में भी को गयी व्यवस्था में भी प्रभावी होगा ।	निरस्त किया जाता है ।
6 (4)--टिप्पणी--उपरोक्त प्रतिबन्ध में स्वर्गीय कर्मचारी की विधवा पत्नी को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्य को पारिवारिक सेवानिवृत्ति वेतन देने की अधिकतम समय अवधि 10 वर्ष है किन्तु यदि किसी कर्मचारी का उत्तराधिकारी (पत्नी को छोड़कर) नेत्रहीन है अथवा हाथ-पैरों से कोई काम करने योग्य नहीं है तो मुख्य नगर अधिकारी उसका निरीक्षण करने के पश्चात् स्वविवेक से उसे आजीवन पारिवारिक पेन्शन स्वीकार कर सकते हैं ।	6 (4)--विकलांग सन्तान केवल नेत्रहीन को ही आजीवन अवधि के लिए पेन्शन देय होगा । शेष विकलांग के सम्बन्ध में प्रशासक/मुख्य/नगर अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा के विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं विकलांग को स्वयं देखकर आजीवन पेन्शन देने के बारे में निर्णय लेंगे, किन्तु पत्नी के पुनः विवाह करने पर पेन्शन देय न होगी ।

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
7--अधिवर्ष निवृत्ति अथवा अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन या उपादान (सुपरएनुएशन रिटायरिंग इनवैलिड एण्ड अदर पेन्शन ओर ग्रेच्युटी) अनुबंध (मैनन के लिए लिखित समुचित धनराशि होगी ।	7--अधिवर्षता स्वेच्छा अथवा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त अथवा अन्य प्रकार प्राप्त पेन्शन/उपादान के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9 (21) (i) के परिभाषित मूल वेतन से होगा, यही व्यवस्था पारिवारिक पेन्शन के सम्बन्ध में लागू होगी । पेन्शन का आगणन सेवा निवृत्ति से पूर्व ठीक दस माह की परिलब्धियों के औसत के आधार पर किया जायेगा । 10 वर्ष अथवा उससे अधिक अर्हकारी सेवा होने पर ही पेन्शन अनुमन्य होगी तथा 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेन्शन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी देय होगी । पेन्शन का आगणन 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा जिसका न्यूनतम 375.00 रुपये अधिकतम 4,500.00 रुपये होगा । औसत परिलब्धि×33/66 अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम होने पर आगणित धनराशि को इस अनुपात में कम करके अनुमन्य की जायेगी । किन्तु न्यूनतम पेन्शन 375 रुपये ही रहेगी । औसत परिलब्धि×अर्हकारी सेवा/66 शिक्षक वर्ग के कर्मचारी जो आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1962 के प्रवृत्त होने के समय नगर निगम (नगर महापालिका) के समय कार्यरत थे जिनकी नियुक्ति प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी द्वारा की गयी थी जिन्होंने उपरोक्त विनियमावली के अन्तर्गत अपना विकल्प दिया था और उस समय पेन्शन पाने योग्य पद पर कार्यरत थे और पेन्शन पाने की पात्रता रखते थे, को ही पेन्शन नगर निगम से देय होगी एवं पेन्शन/उपादान का निस्तारण शासन के शिक्षा विभाग के पेन्शन उपादान सम्बन्धी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा जब सरकारी सेवकों की पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन उपादान के न्यूनतम/अधिकतम निर्धारण मूल वेतन, महंगाई वेतन, अन्तरिम राहत, महंगाई राहत, के सम्बन्ध में जो भी आदेश पारित किये जायेंगे वे प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के आदेश से उसी तिथि से प्रभावी होंगे और प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के ऐसे आदेश आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेनीफिट) विनियम, 1962 का भाग

वर्तमान नियम

प्रस्तावित संशोधन

समस्त मामलों में, जिन मामलों में उक्त विनियम लागू होंगे उन मामलों में राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए जारी आदेश प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी हो सकेंगे ।

अनुबद्ध :

कर्मचारी की पूर्ण छःमाही	सेवा निवृत्ति वेतन सारणी	वार्षिक निवृत्ति वेतन की अधिकतम धनराशि
1	2	3
20	10/60	10,000
21	10. 5/ 60	10,500
22	11/ 60.	11,000
23	11. 5/ 60	11,500
24	12/ 60	12,000
25	12. 5/ 60	12,500
26	13/ 60	13,000
27	13. 5/ 60	13,500
28	14/ 60	14,000
29	14. 5/ 60	14,500
30	15/ 60	15,000
31	15. 5/ 60	15,500
32	16/ 60	16,000
33	16. 5/ 60	16,500
34	17/ 60	17,000
35	17. 5/ 60	17,500
36	18/ 60	18,000
37	18. 5/ 60	18,500
38	19/ 60	19,000
39	19. 5/ 60	19,500
40	20/ 60	20,000
41	20. 5/ 60.	20,500
42	21/ 60	21.000
43	21. 5/ 60	21,500
44	22/ 60	22,000
45	22. 5/ 60	22,500
46	23/ 60	23,000
47	23. 5/ 60	23,500
48	24/ 60	24,000
49	24. 5/ 60	24,500
50	25/ 60	25,000
51	25. 6/ 60	25,500

निरस्त किया जाता है ।

वर्तमान नियम		प्रस्तावित संशोधन
1	2	3
52	26/60	26,000
53	26.5/60	26,500
54	27/60	27,000
55	27.5/60	27,500
56	28/60	28,000
57	28.5/60	28,500
58	29/60	29,000
59	29.5/60	29,500
60	30/60	30,000

7—निम्नलिखित परा विनियम 7(1)क तथा 7(1) ख और जोड़ दिया जाय—

7—(1) दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 तक सेवा निवृत्त महापालिका कर्मचारी/अधिकारी के सेवा निवृत्ति वेतन के स्वीकृत धनांक में निम्नलिखित एतदर्थ (एडहाक) बढ़ोत्तरी की जाती है जो इस संशोधन के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के बाद आगामी मास की पहली तारीख से देय होगी।

निरस्त किया जाता है।

(क) रुपया 200.00 तक स्वीकृत पेन्शन में रुपया 15.00 प्रतिमाह, रु० 200.00 से ऊपर स्वीकृत पेन्शन में रुपया 20.00 प्रतिमाह, पारिवारिक पेन्शन में रुपया 15.00 प्रतिमाह।

निरस्त किया जाता है।

(ख) दिनांक 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक की समय अवधि में सेवा निवृत महापालिका कर्मचारी/अधिकारी के सेवा निवृत वेतन के स्वीकृत धनांक में निम्नलिखित एतदर्थ (एडहाक) बढ़ोत्तरी की जाती है जो गजट में प्रकाशित होने के बाद आगामी पहली तारीख से देय होगी।

निरस्त किया जाता है।

रुपया 200.00 तक स्वीकृत पेन्शन में रुपया 10.00 प्रतिमाह,

रुपया 200.00 से अधिक स्वीकृत पेन्शन में रुपया 15.00 प्रतिमाह,

पारिवारिक में रुपया 15.00 प्रतिमाह।

निरस्त किया जाता है।

(ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में :

निरस्त किया जाता है।

(1) रुपया 100.00 तक प्रतिमाह पेन्शन प्राप्त करने वालों की पेन्शन में रुपया 25.00 प्रतिमाह की वृद्धि,

निरस्त किया जाता है।

(2) रुपया 100.00 से अधिक तथा रुपया 500.00 तक प्रतिमाह पेन्शन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की पेन्शन में रुपया 35.00 प्रतिमाह की वृद्धि,

निरस्त किया जाता है।

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
(3) पारिवारिक पेन्शन में रुपया 100.00 तक देय पेन्शन में रु0 15.00 प्रतिमाह तथा रुपया 100.00 से अधिक देय पेन्शन में रु0 25.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
7—(1) (घ) दिनांक 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में :	निरस्त किया जाता है।
(1) रुपया 100.00 प्रतिमाह पेन्शन प्राप्त करने वालों के पेन्शन मे रुपया 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि;	निरस्त किया जाता है।
(2) रुपया 100.00 से अधिक तथा रुपया 500.00 तक प्रतिमाह पेन्शन प्राप्त करने वालों की पेन्शन में रुपया 20.00 प्रतिमाह की वृद्धि;	निरस्त किया जाता है।
(3) पारिवारिक पेन्शन में रु0 100.00 तक प्रति माह व पेन्शन में रु0 15.00 प्रति माह तथा रु0 100.00 से अधि देय पेन्शन में रु0 20.00 प्रति माह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
7—(1) (ङ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 तक सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति वेतन के स्वीकृत धनांक में निम्नलिखित बढ़ोत्तरी की जाती है :	निरस्त किया जाता है।
(अ) रु0 100.00 तक प्रति माह स्वीकृत पेन्शन पर रु0 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
(ब) रु0 101.00 से रु0 400.00 तक प्रतिमाह स्वीकृत पेन्शन पर रु0 20.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
(स) पारिवारिक स्वीकृत पेन्शन पर 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
7—(1) (च) दिनांक 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1978 तक सेवा-निवृत हुए कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति वेतन के स्वीकृत धनांक में निम्नलिखित बढ़ोत्तरी की जाती है :	निरस्त किया जाता है।
(अ) रुपया 100.00 तक स्वीकृत पेन्शन पर रु0 10.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
(ब) रु0 101.00 से रु0 400.00 तक प्रतिमाह स्वीकृत पेन्शन पर रु015.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
(स) पारिवारिक स्वीकृत पेन्शन पर रु0 10.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
7—(1) (छ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 तक सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों की स्वीकृत मूल सेवा-निवृत्ति वेतन के धनांक में निम्नलिखित अतिरिक्त राहत दी जाती है :	निरस्त किया जाता है।
(1) रु0 100.00 तक मासिक स्वीकृत पेन्शन पर रु0 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि;	निरस्त किया जाता है।

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
(2) रु० 101.00 से रुपया 250.00 तक मासिक स्वीकृत पेन्शन पर रुपया 25.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है ।
(3) रु० 251.00 से रु० 500.00 तक मासिक स्वीकृत पेंशन पर रु० 35.00 प्रतिमाह ।	निरस्त किया जाता है ।
(4) पारिवारिक स्वीकृत पेन्शन पर रु० 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि ।	निरस्त किया जाता है ।
7--(1) (ज) दिनांक 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1980 तक सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के मूल सेवानिवृति वेतन के घनांक में निम्नलिखित राहत दी जाती है :	निरस्त किया जाता है ।
(1) 100.00 रुपया तक स्वीकृत पेन्शन पर रुपया 10.00 प्रतिमाह ।	निरस्त किया जाता है ।
(2) 101.00 रुपया से 250.00 रुपया तक स्वीकृत पेंशन पर रु० 15.00 प्रतिमाह ।	निरस्त किया जाता है ।
(3) 251.00 रुपया से 500.00 रुपया स्वीकृत पेन्शन पर 20.00 रुपया प्रतिमाह ।	निरस्त किया जाता है ।
(4) पारिवारिक स्वीकृत पेन्शन पर 15.00 रुपया प्रतिमाह ।	निरस्त किया जाता है ।
7--(1) (झ) दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1986 तक सेवानिवृत हुए अथवा मृत हुए कर्मचारियों, जिनकी पेन्शन 500.00 रुपया तक स्वीकृत हुई है, उसकी स्वीकृत पेन्शन अथवा पारिवारिक पेन्शन में 10.00 रुपया प्रतिमाह की राहत दी जाती है ।	निरस्त किया जाता है ।
7--(1) (ञ) दिनांक 31 जुलाई, 1986 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिनकी पेन्शन 500.00 रुपया से अधिक है, 35.00 रुपया प्रतिमाह की राहत दिनांक 1 मार्च, 1987 से स्वीकार की जाती है । इस वृद्धि का भुगतान गजट में प्रकाशित होने पर किया जायगा । चूंकि 21 फरवरी, 1987 के गजट में प्रकाशित पेन्शन संशोधन में 500.00 रुपया से अधिक पेन्शन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई राहत प्रदान नहीं की गई थी। अतः उक्त संशोधन स्वीकार किया गया है । उसका संशोधित विनियम निम्न प्रकार है--	निरस्त किया जाता है ।

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
7—(1) (ट) दिनांक 31 जुलाई, 1986 तक सेवा-निवृत कर्मचारी, जिनकी पेन्शन 500.00 रुपया से 1000.00 रुपया तक प्रतिमाह स्वीकार हुई है, की स्वीकृत पेन्शन में 35.00 रुपया प्रतिमाह तथा जिनकी पेन्शन 1001.00 रुपया से 1500.00 रुपया तक प्रतिमाह स्वीकार हुई है, की स्वीकृत पेन्शन में 50.00 रुपया प्रतिमाह की वृद्धि दिनांक 1 मार्च, 1987 से की जाती है। इस वृद्धि का भुगतान गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त किया जायेगा।	निरस्त किया जाता है।
7—(1)(ठ) दिनांक 30 जून, 1986 तक सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की स्वीकृत पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन का 8 प्रतिशत धन राहत के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसकी न्यूनतम सीमा 10.00 रु० तथा अधिकतम सीमा 80.00 रु० प्रतिमाह होगी।	निरस्त किया जाता है।
7—(1)(ड) दिनांक 1 जुलाई, 1986 से 30 जून, 1987 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वीकृत पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन का 5 प्रतिशत धन राहत के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिसकी न्यूनतम सीमा 5.00 रु० तथा अधिकतम सीमा 50.00 रु० प्रतिमाह होगी।	निरस्त किया जाता है।
उक्त क्रमांक 3 की राहत उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित होने पर मार्च, 1988 से देय होगी।	निरस्त किया जाता है।
7—(1)(ण) दिनांक 1 मार्च, 1988 के पश्चात् सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली आगामी राहत किस्तें नगर महापालिका, आगरा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जायेगी।	निरस्त किया जाता है।
7—(1)(त) नगर महापालिका के समस्त सेवा निवृत्त/पारिवारिक पेन्शनरों को राजकीय पेन्शनरों की भांति राजाज्ञा संख्या सा-4-1120/दस-301-87, दिनांक 28 जुलाई, 1987 के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले पेन्शनरों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की पेन्शन को दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनः निर्धारित कर उस पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय पेन्शनरों को दिये जाने वाले समस्त महंगाई राहत व अन्य लाभ दिये जायें। 1 जनवरी, 1986 से 29 फरवरी, 1988 तक सेवा निवृत्त को राज्य सरकार द्वारा राजकीय पेन्शनरों को दिये जाने वाले समस्त महंगाई राहत व अन्य लाभ दिये जायें।	निरस्त किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
13--जिन अधिकारियों पर यह विनियम प्रभावी होंगे उन्हें सामान्य भविष्य निधि का सदस्य होना पड़ेगा जिसके अभिदान के लिए लिखित रूप से मुख्य नगर अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। अभिदान की दर वेतन के 10 प्रतिशत से कम न होगी तथा 20% से अधिक न होगी। अभिदान की दर में परिवर्तन के लिये आवेदन-पत्र मुख्य नगर अधिकारी को किसी वर्ष में मार्च के प्रथम सप्ताह में दिया जायेगा। वर्ष के बीच में दर में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जायेगा।	13--जिन अधिकारियों पर यह विनियम प्रभावी होंगे उन्हें सामान्य भविष्य निधि का सदस्य होना पड़ेगा जिसके अभिदान के लिये लिखित रूप में मुख्य नगर अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। अभिदान की दर वेतन के 10 प्रतिशत से कम न होगी तथा 20 प्रतिशत से अधिक न होगी। अभिदान की दर में परिवर्तन के लिये आवेदन-पत्र मुख्य नगर अधिकारी को किसी वर्ष में मार्च के प्रथम सप्ताह में दिया जायेगा। वर्ष के बीच में दर में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि सेवा निवृत्ति से सामान्य भविष्य निधि के अभिदान की [illegible] बन्द हो जाय।
20--(2) नगर महापालिका, आगरा के प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरान्त महापालिका की सामान्य निधि से रु० 101 पुरस्कार स्वरूप भुगतान किया जाये।	20--(2) नगर निगम, आगरा के प्रत्येक कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के उपरान्त नगर निगम की सामान्य निधि से रु० 251.00 पुरस्कार स्वरूप भुगतान किया जाये।

ये प्रस्तावित संशोधन 1 नवम्बर, 1995 से प्रभावी होंगे तथा ऐसे प्रकरणों पर भी प्रभावी होंगे जो 31 अक्टूबर, 1995 तक अनिर्णीत रहे हों।

राज्य सरकार द्वारा जब-जब सरकारी सेवकों की पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन, उपादान के न्यूनतम/अधिकतम निर्धारण, मूल वेतन, महंगाई वेतन, अन्तरिम राहत महंगाई राहत के सम्बन्ध में जो भी आदेश पारित किए जायेंगे वे प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के आदेश से उसी तिथि से प्रभावी होंगे और प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के ऐसे आदेश आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनिफिट) विनियम, 1962 का भाग समझे जायेंगे। जिन मामलों में उक्त विनियम मौन होंगे उन मामलों में राज्य सरकार के पेन्शनरों के लिए जारी आदेश प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी हो सकेंगे। उपरोक्त संशोधनों की दिनांक 12 अक्टूबर, 1995 को पुष्टि की जा चुकी है।

(ह०) अस्पष्ट,
प्रशासक,
नगर निगम, आगरा।

पी० एस० यू० पी०--62 हिन्दी गजट--भाग 8--1996 ई०।

मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक मुद्रण एवं लेखन-सामग्री उ० प्र०, इलाहाबाद।

आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) विनियम 1962, जो आवश्यक संशोधनों सहित 30 मार्च 1995 के सरकारी गजट में प्रकाशित हुई थीं, में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 548)1(च) के अन्तर्गत निम्न संशोधन) अन्य विनियमों के यथवत रहते हुए प्रस्तावित किये जाते हैं -

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित संशोधन
1(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) 1962 कहा जायेगा ।	1(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्त सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) विनियम 1962 होगा।
	2(2) द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि उन विनियमों में औसत परिलब्धियों की वह ही उपयुक्त परिभाषा मान्य होगी जिसे समय-समय पर राज्य सरकार अपने पेंशनरों के लिए परिभाषित करे ।
4(2) डेथकम (रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) मृत्यु एवं सेवा निवृत्त उपादान	4(2) मृत्यु एवं सेवा निवृत्त उपादान (डेथकम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी ।
यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को, जिन्होने उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या-5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपादान दिया जायेगा (दस वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपादान सर्विसग्रेच्युटी देय होगी) उसकीदर प्रत्येक पुर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी । मृत्यु उपादान सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार की मृत्यु उपादान अनुमन्य होगा, जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों कादो गुना एक से अधिक किन्तु पॉच वर्ष सेकम की सेवा पर परिलब्धियोंका छः गुना, पॉच से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पुर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के अधिक के बराबर बराबर जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (तेंतीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि ढाई लाख रूपये से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा ।	यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को जिन्होने उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या-5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपादान दिया जायेगा (दस वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपादान सर्विस ग्रेच्युटी देय होगी) उसकी दर प्रत्येक पुर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी । मृत्यु उपादान सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को मृत्यु उपादान अनुमन्यहोगा जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का दो गुना एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु पॉच वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का छः गुना, पॉच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष अथवा उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पुर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (तेंतीस) गुने के बराबर होगी किन्तु देय धनराशि ढाई लाख समय से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा ।

क्रमशः.....2.

Scanned with OKEN Scanner

6(2)(ख) अधिकतम रूपया 1250/- प्रतिमाह होगा न्यूनतम धनराशि 375-00 होगी ।

6(2)(ख) पारिवारिक सेवानिवृत्त वेतन (पेंशन) की अधिकतमएवं न्यूनतम प्रतिमाह वह धनराशि होगी जो राज्य सरकार अपने पारिवारिक पेंशनरों के लिए समय समय पर निर्धारित करे ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि पारिवारिक सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) की न्यूनतम धनराशि से सम्बन्धित अधिकारी को उसकीसेवानिवृत्ति पर स्वीकृति होने वाले सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) की धनराशि से अधिक न होगी, अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाये तो सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) उस धनराशि से अधिक न होगी जो उसे मृत्यु के बाद वाले दिन सेवानिवृत्त होने पर निवृत्ति वेतन के समय में प्राप्त होता ।

यह प्रतिबन्ध निरस्त किया जाता है जो दिनांक 1.11.95 से प्रभावी होगा ।

7(1)(त) निरस्त किया जाता है ।

7(1)(त) नगर निगम के समस्त सेवानिवृत्ति/पारिवारिक पेंशनरों को राजकीय पेंशनरों की भाँति राजाज्ञा सा-4-1120/दस-301-87 दिनांक 28 जुलाई 1987 के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन कोदिनांक 1 जनवरी 1986 से पुनः निर्धारित कर उस पर समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय पेंशनरों को दिये जाने वाले मंहगाई राहत व अन्य लाभ दिये जायें । । जनवरी, 1986 से 29 फरवरी, 1988 तक सेवानिवृत्त को राज्य सरकार द्वारा राजकीय पेंशनरों को दिये जाने वाले समस्त मंहगाई राहत व अन्य लाभ अनुमन्य होंगे ।

9 प्रतिबन्ध यह है कि संराशिकरण के बाद देय सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) की धनराशि किसी भी दशा में सिविल सर्विस रेगुलेशन के अन्तर्नियम 474 तथा 474ए के अन्तर्गत निकलने वाले सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) के आधे अथवा 50 रूपया से जो भी अधिक हो कम न होगी ।

9. प्रतिबन्ध यह है कि संराशिकरण के बाद देय पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में सिविल सर्विस रेगुलेशन के अन्तर्नियम 474 व 474ए के अन्तर्गत केलकुलेटिड पेंशन के आधे से कम न होगी ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि संराशिकरण की धनराशि पेंशन का वह भाग होगी जैसा राज्य सरकार समय-समय पर अपने पेंशनरों के लिए निर्धारित करे ।

11. पेंशन अंशदान के समय में नियमित कर्मचारियों के मूल वेतन का 15 प्रतिशत धन पेंशन निधि में जमा किया जायेगा ।

11. पेंशन अंशदान के समय में नियमित कर्मचारियों के मूल वेतन तथा मंहगाई राहत का 15 प्रतिशत धन पेंशन निधि में जमा किया जायेगा ।

क्रमशः.....3.

Scanned with OKEN Scanner

20(2) नगर निगम आगरा के प्रत्येक कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के उपरान्त नगर निगम की सामान्य निधि से रूपया 251/- पुरुस्कार स्वरूप भुगतान किये जायें ।

20(2) नगर निगम आगरा के प्रत्येक कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के उपरान्त नगर निगम की सामान्य निधि से 31.10.1997 से सेवारत निवृत्त के समय 501/- पुरुस्कार स्वरूप भुगतान किये जायें ।

20(3) नगर निगम आगरा के वे पेंशनर जो सेवा निवृत्ति के पश्चात अन्य जनपदों में आवासित हो गये हैं और जिन्हें वृद्धावस्था के कारण लम्बी यात्रा में काफी असुविधा होती है उनके मामलों में उनके द्वारा अपने आवासित नगर की भारतीय स्टेट बैंक में पेंशन खाता खुलवाने पर उनकी पेंशन सम्बन्धित बैंक को चैक अथवा ड्राफट द्वारा (ड्राफ्ट की व रजिस्ट्री व्यय की कटौतीकर) 5 माह तक प्रेषित की जा सकेगी परन्तु उन्हें प्रत्येक अप्रैल एवं अक्टूबर मास में स्वयं नगर निगम आगरा में उपस्थित होकर जीवित होने के प्रमाण देना होगा । नगर निगम द्वारा सम्बन्धित बैंक को यह भी सूचित किया जायेगा कि सम्बन्धित पेंशनर के जीवित होने की दशा में ही सप्रेषित पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जाये अन्यथा पेंशन की धनराशि नगर निगम आगरा को वापस कर दी जाये ।

उपरोक्त संशोधन 01.11.1997 से प्रभावी समझे जायेंगे । संशोधन का प्रस्ताव नगर निगम के 18 वें अधिवेशन की बैठक दि नांक 3.9.98 में प्रस्ताव संख्या 4(1.1) के अन्तर्गत स्वीकृत किया

मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम, आगरा

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या– 237 (ख–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एरा०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 13 अक्टूबर, 2010
आश्विन 21, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

राख्या सा–3–1558 / दस–2010–301(9)-2003 टी०सी०
लखनऊ, 13 अक्टूबर, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

अधिसूचना संख्या–सा–3–379 / दस–2005–301(9) / 2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा शासन के नियत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व तत्समय राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी, और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद आने वाले स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2–उपर्युक्त संदर्भ में केन्द्रीय लेखा–अनुरक्षक एजेन्सी की समुचित व्यवस्था होने और पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति होने तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में उपर्युक्त संस्थाओं के कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्त परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यपाल महोदय निम्नवत् आदेश देते हैं :–

(1) यह व्यवस्था दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन, महँगाई वेतन तथा महँगाई भत्ते / दिनाँक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन एवं ग्रेड पे तथा दोनों के योग पर महँगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान (निकटतम रूपये में पूर्णांकित) योजनान्तर्गत पेंशन टियर–1 के लिए करेगा। इस अंशदान की कटौती संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कर्मचारी के वेतन से की जायेगी। इन कर्मचारियों पर सामान्य भविष्य निधि योजना लागू न होने के कारण इनके वेतन से सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के रूप में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(2) प्रत्येक कर्मचारी द्वारा योजना हेतु आवेदन – पत्र (प्रपत्र–1 ख) तीन प्रतियों में तथा संलग्न प्रारूप में नामांकन किया जायेगा, जिसे योजना की सीमान्तर्गत आवश्यतानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा। नामांकन के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका / सेवा अभिलेख में भी की जायेगी।

(3) संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, (जिन्हें आगे सक्षम अधिकारी कहा गया है) दिनॉक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आये प्रत्येक कर्मचारी के लिए निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ से इन आदेशों के जारी होने के एक माह के अन्दर "इन्डेक्स नम्बर" प्राप्त कर लें। तत्पश्चात् नये कर्मचारी जैसे ही सेवा में कार्यभार ग्रहण करें, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के अन्दर "इन्डेक्स नम्बर" प्राप्त कर लिया जाए।

(4) उपरोक्त योजना से सम्बन्धित लेखों का रख–रखाव निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उसी प्रकार से किया जायेगा, जैसा कि नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के संबंध में किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी से निर्धारित फार्म (प्रपत्र–1 ख), पर आवेदन–पत्र तीन प्रतियों में प्राप्त होने पर निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पेंशन योजना में सम्मिलित प्रत्येक कर्मचारी को "इन्डेक्स नम्बर" आवंटित किया जायेगा। निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आवेदन – पत्र की एक प्रति आवंटित इंडेक्स नम्बर सहित संबंधित संस्था को वापस की जायेगी। पेंशन योजना हेतु आबंटित "इन्डेक्स नम्बर" कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के साथ अंकित कर दिया जायेगा।

(5) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए वेतन से कटौती, कर्मचारी द्वारा जिस माह में कार्यभार ग्रहण किया जाये, उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्भ होगी, अर्थात् जिस माह में कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जायेगा, उस माह के लिए कटौती नहीं की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कर्मचारी माह अप्रैल, 2005 में सेवा में आया है, उसके वेतन से अंशदान की कटौती माह मई, 2005 के वेतन से प्रारम्भ होगी। दिनॉक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों से वर्तमान मासिक अंशदान के साथ–साथ अवशेष एक माह के अंशदान, यदि कोई हो, की कटौती भी वेतन से कर ली जायेगी। इसके समतुल्य धनराशि का अंशदान राज्य सरकार / सेवायोजक द्वारा जमा किया जायेगा।

(6)(क) उपर्युक्त कर्मचारियों के वेतन अनुदान बिल, अन्य कर्मचारियों के वेतन अनुदान बिल से अलग तैयार कर पारण हेतु प्रतिमाह कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन अनुदान बिल के साथ, पेंशन योजना के लिए अंशदान की कटौती का शेड्यूल निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र 2–ग(1)) पर तीन प्रतियों में संलग्न किया जायेगा। योजना से आच्छादित अधिष्ठान के सभी कर्मचारियों के संबंध में प्रविष्टियॉ शेडयूल में की जायेंगी, भले ही किसी का वेतन किसी कारण आहरित न किया जा रहा हो और उसके अंशदान की राशि शून्य हो।

वेतन अनुदान बिल में समस्त संबंधित कर्मचारियों के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती की कुल राशि प्रपत्र 2–ग(1) (दो प्रतियों में), जो इस प्रयोजनार्थ चालान का प्रपत्र भी होगा पर, इस हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष, जिसका विवरण आगे दिया गया में जमा किया जायेगा। शेड्यूल की एक प्रति कोषागार द्वारा अलग कर रख ली जायेगी। कोषागार स्तर पर नयी पेंशन योजना को संबंधित मॉड्यूल में, शेड्यूल के अनुसार कर्मचारी बार प्रविष्टि की जायेगी। इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–सा–3–1454 / दस– 2008–301(9) / 2003, दिनॉक 28–11–2008 में दी गयी प्रकिया का अनुपालन किया जायेगा। इस संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:–

(i) संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वेतन बिल के साथ संलग्न, मुख्य लेखाशीर्ष "8342– अन्य जमा " के अन्तर्गत कटौतियों से संबंधित शेड्यूल निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र 2–घ(1)) में स्पष्ट एवं कम्प्यूटराइज्ड बनाए गए हों।

Scanned with OKEN Scanner

(ii) संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वेतन बिल से की गयी कटौती के अनुसार लेखाशीर्ष "8342 – अन्य जमा – 120–विविध जमा –02– सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना 02– शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1" को संकमित की जाने वाली राशि शुद्ध है तथा शेड्यूल तदनुसार बनाये गये हैं।

(ख) प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रदेश के अन्दर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वाह्य सेवा योजकों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के पेंशनरी अंशदान की धनराशि चालान के माध्यम से कोषागार में जमा नहीं की जायेगी। ऐसे बाह्य सेवायोजक द्वारा कर्मचारी के वेतन से पेंशनरी अंशदान की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तथा संबंधित शेड्यूल–2(ग–1) पर कार्मिक वार कटौती का पूर्ण विवरण प्रविष्ट करते हुए निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अगले माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जायेगा।

पेंशन, निदेशक द्वारा संबंधित कर्मचारी के पेंशनरी अंशदान से संबंधित बैंक ड्राफ्ट शिड्यूल–2(ग–1) के साथ कोषागार में जमा किया जायेगा। नियोक्ता अंशदान जमा करने के लिए निदेशक, पेंशन द्वारा देयक अनुदान संख्या – 62 के लेखाशीर्षक – 2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01–सिविल–117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिये सरकारी अंशदान–03–राज्य सरकार का अंशदान–03–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता पर बनाकर जवाहर भवन कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।

(ग) ऐसे बाह्य सेवा योजक जिनके द्वारा शासनादेश दिनांक 09–11–2006 के अनुसार बाह्य सेवायोजक का अंशदान जमा किया जाना है, उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी के अंशदान की धनराशि अनुलग्नक–2(ग–1) तथा बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि अनुलग्नक–2(ध–1) सहित (चाहे बाह्य सेवायोजक कार्यालय प्रदेश के अन्दर स्थित हो या बाहर) प्रतिमाह निदेशक, पेंशन के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक भेजा जायेगा। ड्राफ्ट की धनराशि को लेखाशीर्षक – 8342 में जमा कर। की कार्यवाही निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

(7) यदि किसी कर्मचारी से किसी माह में पेंशन के लिए अंशदान की कटौती नहीं की जाती है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कटौती के शेड्यूल में अंशदान की कटौती शून्य दर्शाते हुए उसके स्पष्ट कारणों का निश्चित रूप से उल्लेख कर दिया जायेगा।

(8) वेतन अनुदान बिल से पेंशन के लिए अंशदान हेतु की गयी कटौती की धनराशि लोक–लेखा पक्ष में निम्नांकित लेखाशीर्ष में अन्तरण द्वारा जमा की जायेगी :–

मुख्य शीर्ष	8342–अन्य जमा –
लघु शीर्ष	120–विविध जमा
उप शीर्ष	02– सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना
विस्तृत शीर्ष	02– शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1

(9) संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रेषित किए गए शेड्यूल की एक प्रति को, यथा स्थिति, कोषाधिकारी / भुगतान एवं लेखाधिकारी द्वारा अलग करके एक अलग कवर में प्रत्येक माह एक कवरिंग शीट जिसमें संस्थावार अंशदान की कुल राशि का उल्लेख हो, के साथ कार्यालय निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ को सापट कापी के साथ भेजा जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(10) उप–प्रस्तर – 6(ग) से आच्छादित मामलों के अतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान के समतुल्य (मैचिंग) अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस हेतु दिनाँक 28–11–2008 के शासनादेश के प्रस्तर–(2) एवं (3) में दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

(11)(क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारी के अंशदान के समतुल्य राज्य सरकार के अंशदान हेतु (ऐसी बाह्य सेवा की अवधि के लिए भी जिसके संबंध में बाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशनरी अंशदान देय नहीं है) प्रति माह निम्नांकित लेखाशीर्ष को "डेबिट" किया जायेगा :–

मुख्य शीर्ष	2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ –
उप मुख्य शीर्ष	01–सिविल –
लघु शीर्ष	117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान
उप शीर्ष	03– राज्य सरकार का अंशदान
विस्तृत शीर्ष	03– शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान
मानक मद	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।

उपर्युक्त लेखाशीर्ष से डेबिट की गयी राशि "बुक ट्रांसफर" द्वारा लेखाशीर्ष 8342–अन्य जमा–120–विविध जमा–02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–04–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार का अंशदान–टियर–1" में जमा की जायेगी।

कर्मचारी का अंशदान जिस माह के वेतन से काटा गया हो, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार का मासिक अंशदान सामान्यतः जिस माह के लिए कर्मचारी का अंशदान काटा गया हो, के अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ मान लिया जायेगा, चाहे ही वास्तव में किसी अन्य दिनाँक को जमा किया गया हो, परन्तु इस प्रयोजनार्थ मात्र इन्डेक्स नम्बर आबंटित होने के पूर्व की अवधि के अवशेष अंशदान का माह वही माना जायेगा, जिसमें अवशेष अंशदान वास्तव में जमा किया गया हो अथवा जिस माह के अंशदान के साथ कर्मचारी का अवशेष अंशदान वेतन से काटकर जमा किया गया हो। उदाहरण के रूप में यदि ऐसा अवशेष अंशदान सीधे चालान के माध्यम से माह जून में जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का समतुल्य अंशदान दिनाँक 01 जुलाई को जमा माना जायेगा तथा यदि अवशेष अंशदान माह सितम्बर के मासिक अंशदान के साथ वेतन से काटकर जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का अंशदान 01 अक्टूबर को जमा माना जायेगा। स्थानान्तरण की दशा में अन्तिम वेतन पर्ची (एल0पी0सी0) में इस स्थिति का उल्लेख किया जाए कि किस माह तक अंशदान काटा गया है। यदि किसी माह / अवधि के अंशदान की कटौती अवशेष हो, तो उसे अन्तिम वेतन पर्ची पर अलग टिप्पणी के रूप में दर्शाया जायेगा।

(ख) ऐसी बाह्य सेवा जिसके लिये पेंशन अंशदान देय नहीं है, बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कर्मचारी का चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा अंशदान भी, जिस माह के वेतन से कटा हो, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जाएगा।

(12) पेंशन निधि में जमा कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान पर राज्य सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि के संबंध में निर्धारित दर पर वार्षिक ब्याज अनुमन्य होगा। ब्याज की गणना उसी आधार पर की जायेगी जैसे सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खाते में जमा धनराशि पर की जाती है।

(13) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वर्ष के अन्त में ब्याज का भुगतान निम्नांकित लेखाशीर्ष को डेबिट कर "बुक ट्रांसफर" द्वारा संबंधित खातों में जमा किया जायेगा:–

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा–3–1558/दस–2010–301(9)/2003 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 13 अक्टूबर, 2010

अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व तत्समय राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी, और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद आने वाले स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं में इस शासनादेशों में दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल कर लें।

3–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने स्तर से इस शासनादेश के अनुपालन हेतु कोषाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कोषागार पैकेज में यथेष्ट संशोधन करवाने का कष्ट करें।

6–निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, लखनऊ।

7–निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

8–निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

9–निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

10–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

11–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0, लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य शीर्ष	2049–ब्याज अदायगियाँ –
उप मुख्य शीर्ष	03–अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज–
लघु शीर्ष	117 – निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम पर ब्याज –
उप शीर्ष	03–निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना निधि में जमा राशि पर ब्याज
विस्तृत शीर्ष	03– शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना निधि में जमा राशि पर ब्याज।
मानक मद	32–ब्याज/लगाश

(14) वर्ष के अन्त में, निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट (दो प्रतियों में) सम्बन्धित संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी को भेजा जायेगा जिसमें प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी / राज्य सरकार का अलग–अलग मासिक अंशदान, ब्याज की धनराशि तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। स्टेटमेन्ट की एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

(15) सम्बन्धित संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी /कार्यालयाध्यक्ष /आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त 'इन्डेक्स नम्बर' के अनुसार प्रपत्र–3 में निर्धारित प्रारूप में एक लेजर रखा जायेगा जिसमें कर्मचारी का वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान की धनराशि, ब्याज तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जी0पी0एफ0 पास–बुक की भाँति प्रपत्र–4 में निर्धारित प्रारूप पर अंशदायी पेंशन पास बुक भी रखी जायेगी। निदेशक, पेंशन से प्राप्त स्टेटमेन्ट तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर रखे जाने वाले लेखों में यदि कोई अन्तर हो तो उसका निदेशक, पेंशन के कार्यालय से वर्ष प्रतिवर्ष समाधान किया जायेगा।

(16) उपर्युक्त अन्तरिम व्यवस्था के दौरान योजना में प्रावधानित स्वैच्छिक टियर–II खाते का संचालन नहीं किया जायेगा।

3–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु जो शासकीय अधिकारी अनुदान बिल प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत हों, वे नियमित रूप से यह समीक्षा करते रहेंगे कि संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के वेतन अनुदान बिल मासिक आधार पर कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें।

4–कृपया शासन के इन आदेशों का अनुपालन समस्त संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

आज्ञा से,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव वित्त।

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र 1-ख

उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु आवेदन-पत्र

(संदर्भ : शासनादेश संख्या सा–3–1558/दस–2010–301(9)/2003 टी0सी0, दिनांक 13 अक्टूबर, 2010)

परिभाषित अंशदान योजना इन्डेक्स नम्बर .....

(पेंशन निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आवंटित किया जायेगा)

1 आवेदक का नाम (हिन्दी में) .....

अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) .....

2 आवेदक के पिता/पति का नाम .....

3 लिंग : पुरुष ☐ स्त्री ☐

4 वैवाहिक स्थिति : विवाहित ☐ अविवाहित ☐

5 पदनाम :

6 कार्यालय का नाम :

7 आवेदक का सेवा संवर्ग :

8 सेवा में आने की तिथि :

9 वेतनमान :

10 मूल वेतन :

11 जन्म तिथि :

12 क्या नियमित नियुक्ति है : हाँ ☐ नहीं ☐

13 श्रेणी– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य

पिछड़ा वर्ग/अन्य : (सांख्यिकीय उपयोग के लिए) ☐

14 क्या नामांकन संलग्न है : हाँ ☐ नहीं ☐

15 टिप्पणी, यदि कोई हो :

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का [redacted] करते

[redacted] उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुति

प्रमाण-पत्र जो कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) श्री/श्रीमती/कुमारी..... नियमित कर्मचारी है एवं आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सही हैं।

(2) श्री/श्रीमती/कुमारी..... उत्तर प्रदेश सरकार की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूर्ण पता/कार्यालय की मुहर सहित

स्थान :

दिनांक :

टिप्पणी :–

1–उपर्युक्त आवेदन-पत्र पेंशन निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को दो प्रतियों में भेजा जायेगा।

2–आवेदक कर्मचारी वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त होने की दशा में वाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशन निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को दो प्रतियों में आवेदन-पत्र संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से ही भेजा जायेगा।

(प्रपत्र 1, क्रम के साथ)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नक
(प्रपत्र 1-ख के साथ)

नामांकन प्रपत्र

(उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु नामांकन)

इस प्रपत्र को भरने से पूर्व कृपया इसके दूसरी ओर छपे हुए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लिए जाएं

पेंशन योजना इकाई कस्टमर नम्बर.....

मैं ..... एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं अथवा आश्रित माता-पिता, बहन-भाई है, योजना में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ जब उस धनराशि के देय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाय या देय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाय :–

नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पूरा पता	अभिदाता से सम्बन्ध	नामित व्यक्ति की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति का देय अंश (शेयर)	आकस्मिकताएं, जिनके होने पर नाम अवैध हो जायेगा	यदि अभिदाता की मृत्यु से पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, तो इस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते और सम्बन्ध यदि कोई हो, जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।
1	2	3	4	5	6
1–					
2–					
3–					
4–					

दिनांक ..... मास.....20

स्थान.....

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

नाम पता हस्ताक्षर

1–

2–

अभिदाता के हस्ताक्षर

नाम : (हिन्दी में).....

(अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में).....

पदनाम.....

पदनाम.....

द्वारा नामांकन प्रपत्र की प्राप्ति का दिनांक.....

अभिदाता के हस्ताक्षर :--..

(क) अभिदाता का पूरा नाम भरा जाय।

(ख) 'परिवार' का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा।

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियां तथा बच्चे एवं अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे, किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पार्थक्य (Judicial Separation) हो चुका है अथवा वह जिस समुदाय की है, उसकी रूढ़िगत विधि के अधीन भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं रह गई है, तो वह एतदपश्चात् अभिदाता का परिवार की सदस्य नहीं मानी जायेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित रूप से स्पष्ट अधिसूचना (Express Notification) द्वारा यह सूचित न करें कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति तथा बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे, किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता लिखित अधिसूचना द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में सम्मिलित न किये जाने की इच्छा व्यक्त कर देती है तो पति को एतदपश्चात् अभिदाता के परिवार का सदस्य न माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में उसे सम्मिलित न किये जाने हेतु अपनी अधिसूचना का औपचारिक रूप से लिखकर रद्द न कर दें।

टिप्पणी :—

(1) "बच्चों" का तात्पर्य वैध बच्चों से है।

(2) कोई दत्तक बच्चा तभी बच्चा माना जायेगा जब दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किन्तु, यदि कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो यह तभी मान्य होगा जब सरकार के विधि परामर्शी को इस बात का समाधान हो जाय कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन दत्तक ग्रहण को 'जारज बच्चे' (Natural Child) की प्रास्थिति (Status) प्रदान करने के लिए विधिक मान्यता प्राप्त है।

(ग) यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा' लिखा जाय। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश जिसमें पेंशन खाते की सम्पूर्ण देय धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाय।

(घ) स्तम्भ-5 में आकस्मिकता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु का उल्लेख न किया जाय।

(ङ) स्तम्भ-6 में अभिदाता के नाम का उल्लेख न किया जाय।

(च) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे के खाली स्थान के आर-पार लकीर खींच दी जाय, जिससे कि अभिदाता के हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र 2-ग (1)

वाउचर/चालान संख्या .....
दिनांक .....
(कोषागार/बैंक द्वारा भरा जायगा)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (स्वायत्तशासी संस्था)

वेतन से अंशदान कटौती का शेड्यूल/चालान माह.....20

जिला कोषागार/भुगतान एवं लेखाधिकारी

कोषागार कोड :

संस्था /कार्यालय का नाम .....

आहरण/वितरण अधिकारी पदनाम.....

आहरण/वितरण अधिकारी कोड :

मुख्य लेखाशीर्ष :

अनुदान संख्या.

मुख्य शीर्ष	"8342–अन्य जमा –
लघु शीर्ष	120–विविध जमा
उप शीर्ष	02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना
विस्तृत शीर्ष	02–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का अंशदान –"टियर–I"
	8 3 4 2 1 2 0 0 2 0 2 0 0

क्रम संख्या	परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर	नाम/पदनाम	मूल वेतन	महंगाई वेतन	महंगाई भत्ता	योग	कर्मचारी का अंशदान			अभ्युक्ति
							वर्तमान	एरियर		
								माह/वर्ष	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कालम–4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका तथा वेतन बिल से सत्यापित है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्देश :

1- वेतन एवं भत्तों के आहरण न होने की स्थिति में कालम–4 से 10 तक 'निल' प्रविष्टि दर्शायी जाय, किन्तु कालम–1 से 3 तक की प्रविष्टि अवश्य की जाये।

2- कालम (2) : परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर सही दर्शाया जाना चाहिए।

3- कालम (3) : नाम एवं पदनाम सेवा पुस्तिका के अनुसार होना चाहिए।

4- कालम (4), (5) तथा (6) सम्बन्धित माह में आहरित वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता ही दर्शाया जाना चाहिए।

5- कालम (8) तथ (9) : कर्मचारी का अंशदान, एरियर वेतन बिल तथा पुंनरीक्षित महंगाई भत्ता एरियर बिल से भी काटा जाय।

6- किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण अथवा किसी अन्य कार्यालय से स्थानान्तरित होने की दशा में कर्मचारी के नाम के सामने अभ्युक्ति कालम में लगातार दो माह तक यह तथ्य दर्शाया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–2 (घ–1)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (स्वायत्तशासी संस्था)

राज्य सरकार / संवायोजक के अंश ..... से संयुक्त / चालान माह 20

वेतन बिल / भुगतान एवं लेखाधिकारी कोषागार कोड

कार्यालय / संस्था का नाम .....
आहरण / वितरण अधिकारी (पदनाम) .....

लेखाशीर्ष	8342–अन्य जमा
लघु शीर्ष	120–विविध जमा
उपशीर्ष	02– सहायता प्राप्त शैक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना।
वस्तु शीर्ष	04–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार का अंशदान

8	3	4	2	1	2	0	0	2	0	4	0	0

क्रम संख्या	परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर	नाम / पदनाम	मूल वेतन	महगाई वेतन	महगाई भत्ता	योग	कर्मचारी का अंशदान			अन्युक्ति
							वर्तमान	एरियर		
								माह / वर्ष	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कालम–4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि संवापुस्तिका तथा वेतन बिल से सत्यापित है।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम सहित।

उत्तर प्रदेश असाधारण, 13 अक्टूबर, 2010

Scanned with OKEN Scanner

कर्मचारी का नाम

भुगतान का मास	वेतन / इकाएं वेतन / महंगाई भत्ते की सम्बद्ध अवधि	कोषागार बाउचर / चालान संख्या और दिनांक	धनराशि											
1	2	3	4	5	6									
अप्रैल														
मई														
जून														
जुलाई														
अगस्त														
सितम्बर														
अक्टूबर														
नवम्बर														
दिसम्बर														
जनवरी														
फरवरी														
मार्च														
योग														
**														
** योग														

वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे

क– प्रारंभिक शेष जोड़िए .....

ख– (1) वर्ष में नियमित जमा .....

(2) प्रारंभिक शेष एवं नियमित जमा पर ब्याज .....

(3) वर्ष में अवशेष जमा .....

(4) अवशेष जमा पर ब्याज .....

(5) योग (1 से 4 तक) .....

महायोग (क+ख) (5) .....

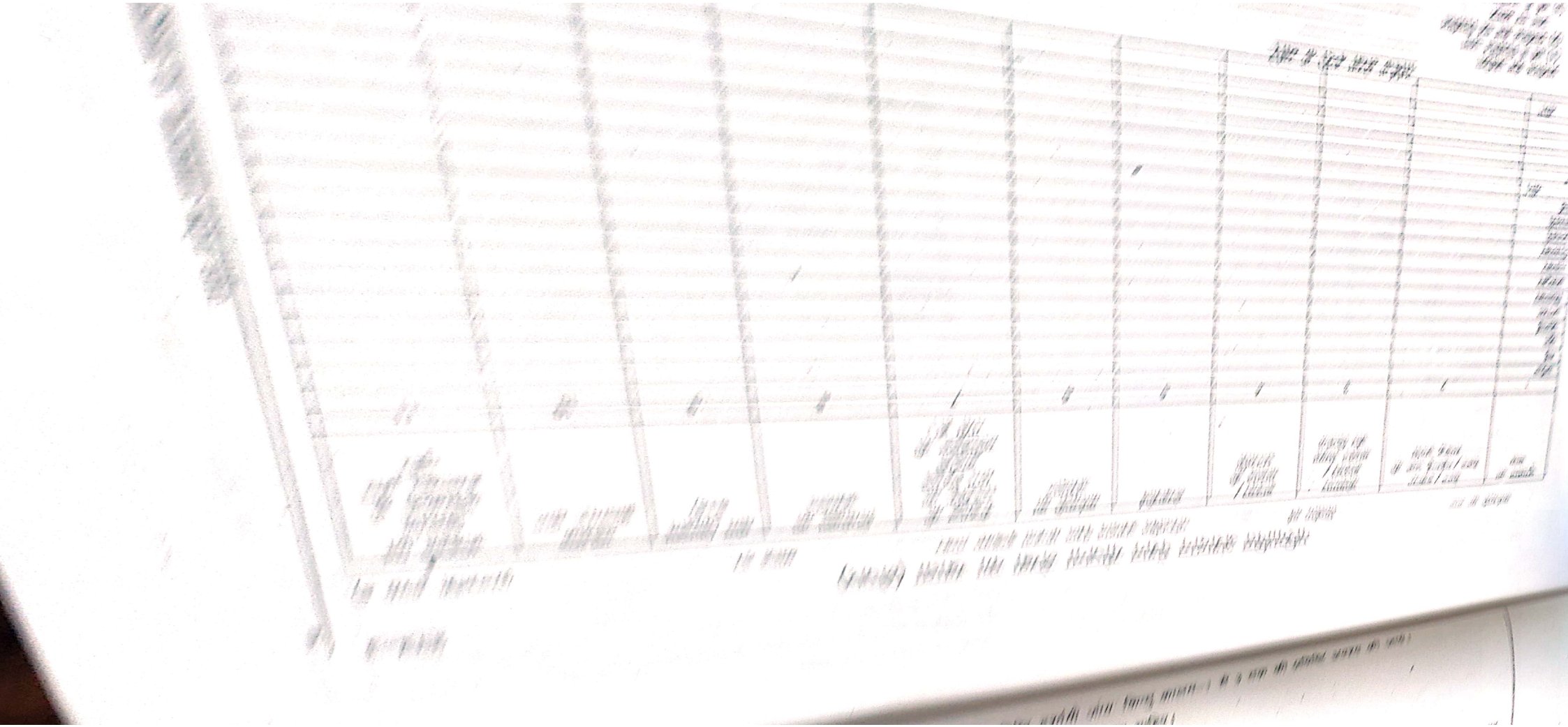
सत्यापन

.....द्वारा सत्यापन किय

.....द्वारा प्रति हस्ताक्ष

कार्यालयाध्यक्ष /
अधिकारी की

नियमित वेतन बिलों के अलावा अवशेष वेतन, अवशेष महंगाई वेतन एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की कटौती से सम्बंधित विवरण अंकित किये
ब्याज सम्बद्ध अवधि के अनुसार आगणित किया जायेगा।



Scanned with OKEN Scanner

1- वेतन एवं भत्तों के आहरण न होने की स्थिति में कालम–4 से 10 तक 'निल' प्रविष्टि दर्शायी जाय; किन्तु कालम–1 से 3 तक की प्रविष्टि अवश्य की जाये।

2- कालम (2) : परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर सही दर्शाया जाना चाहिए।

3- कालम (3) : नाम एवं पदनाम सेवा पुस्तिका के अनुसार होना चाहिए।

4- कालम (4), (5) तथा (6) सम्बन्धित माह में आहरित वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता ही दर्शाया जाना चाहिए।

5- कालम (8) तथ (9) : कर्मचारी का अंशदान, एरियर वेतन बिल तथा पुंनरीक्षित महंगाई भत्ता एरियर बिल से भी काटा जाय।

6- किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण अथवा किसी अन्य कार्यालय से स्थानान्तरित होने की दशा में कर्मचारी के नाम के सामने अभ्युक्ति कालम में लगातार दो माह तक यह तथ्य दर्शाया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लेखा का खाता (लेजर)

प्रपत्र–3

कर्मचारी का नाम ..... वित्तीय वर्ष..... परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर..... ब्याज दर..... (धनराशि रुपये में)

भुगतान का मास	वेतन/डकारू वेतन/महंगाई भत्ते की सम्बद्ध अवधि	कोषागार बाउचर/ चालान संख्या और दिनांक	बाउचर/ चालान की धनराशि	लेखाशीर्ष	कर्मचारी का अंशदान	शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गयी हो।	नियोक्ता का अंशदान	योग (कालम 6+8)	मासिक क्रमागत योग	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अप्रैल										
मई										
जून										
जुलाई										
अगस्त										
सितम्बर										
अक्टूबर										
नवम्बर										
दिसम्बर										
जनवरी										
फरवरी										
मार्च										
योग										
**										
** योग										

वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे

क– प्रारंभिक शेष जोड़िए .....

ख– (1) वर्ष में नियमित जमा .....

(2) प्रारंभिक शेष एवं नियमित जमा पर ब्याज .....

(3) वर्ष में अवशेष जमा .....

(4) अवशेष जमा पर ब्याज .....

(5) योग (1 से 4 तक) .....

महायोग (क+ख) (5) .....

सत्यापन

.....द्वारा सत्यापन किया गया।

.....द्वारा प्रति हस्ताक्षरित।

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

*नियमित वेतन बिलों के अलावा अवशेष वेतन, अवशेष महंगाई वेतन एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की कटौती से सम्बंधित विवरण अंकित किये ब्याज सम्बद्ध अवधि के अनुसार आगणित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण ब्यौरे

अभिदाता का नाम .....

पेंशन निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा
आवंटित इन्डेक्स नम्बर .....

पास–बुक जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

पास–बुक जारी किये जाने का दिनांक

अभिदाता का निजी विवरण

1. नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. जन्मतिथि .....
4. (क) स्थाई पता .....
   .....
   (ख) अस्थाई पता .....
   .....
5. संस्था के अधीन सेवा में प्रवेश करने का दिनांक .....
   .....
6. परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में अभिदान प्रारम्भ होने का दिनांक .....
7. अभिदाता के हस्ताक्षर का नमूना (जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष लिये जायेंगे)
8. पास-बुक जारी करने वाले उस अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर जो अभिदाता के हस्ताक्षर को प्रमाणित करे।

   हस्ताक्षर–
   दिनांक–
   मुहर–

9. सेवा छोड़ने का दिनांक .....
10. सेवा छोड़ने का कारण (त्याग–पत्र/सेवा से हटाया जाना/अधिवर्षता superannuation)/मृत्यु आदि)

Scanned with OKEN Scanner

(धनराशि रुपये में)

क्रम सं.	वेतन/बकाया वेतन/महंगाई भत्ते की सम्बद्ध अवधि	कोषागार चालान/ हस्तान्तरण सत्यापन की दिनांक	कोषागार/ उपकोषागार की प्रविष्टि	वेतन/पेंशन	कटौती का आहरण	शेड्यूल की प्रविष्टि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गई हो।	राज्य सरकार/ निगमों का अंशदान	योग (6-8)	अभिलेख प्रति	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अप्रैल										
मई										
जून										
जुलाई										
अगस्त										
सितम्बर										
अक्टूबर										
नवम्बर										
दिसम्बर										
जनवरी										
फरवरी										
मार्च										
योग										
**										
** योग										

वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे

क– प्रारम्भिक शेष
जोडिए
ख - (1) वर्ष में नियमित जमा .....
(2) प्रारम्भिक शेष एवं नियमित जमा पर ब्याज .....
(3) वर्ष में अवशेष जमा .....
(4) अवशेष जमा पर ब्याज .....
(5) योग (1 से 4 तक) .....
निकासी (क–ख) (6) .....

**निलम्बित वेतन बिल के अन्तर्गत अवशेष वेतन अदत्त महंगाई वेतन एवं अन्तरिम राहत/महंगाई भत्ते से अशदान की कटौती से सम्बन्धित विवरण अंकित किए जायेंगे। ब्याज सम्बन्धित अवधि के अनुसार आगणित किया जायेगा।

सत्यापन

..... द्वारा सत्यापन किया गया।
..... द्वारा प्रति हस्ताक्षरित।

आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

(1) मेरे द्वारा पासबुक का प्रथम निरीक्षण दिनांक ..... को किया गया।

अभिदाता के हस्ताक्षर

(2) मेरे द्वारा पासबुक का द्वितीय निरीक्षण दिनांक ..... को किया गया।

अभिदाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र–4

(संस्था का नाम)

अंशदायी पेंशन पास–बुक

नाम _____

परिभाषित अंशदान पेंशन इन्डेक्स नम्बर _____

_____

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय – ज्ञाप संख्या–सा–3–1558 / दस–2010–301(9)2003 टी0सी0, दिनांक– 13 अक्टूबर, 2010 द्वारा निर्धारित।

Scanned with OKEN Scanner

तैनाती एवं स्थानान्तरण के ब्यौरे

क्रम संख्या	अवधि		पद जिस पर कार्य किया	कार्यालय का नाम	प्रमाणित करने वाले कार्यालयाध्यक्ष के दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर
	कब से	कब तक			
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Scanned with OKEN Scanner

परिवार का विस्तृत विवरण

क्रम संख्या	नाम	सम्बंध	जन्मतिथि	अभिदाता के हस्ताक्षर	कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या	अवधि		पद जिस पर कार्य किया	कार्यालय का नाम	प्रमाणित करने वाले कार्यालयाध्यक्ष के दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर
	कब से	कब तक			
1	2	3	4	5	6
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 699 राजपत्र (हि०)–2010–(1407)–597–(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 93 सा0 वित्त–2010–(1408)–10,000–(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्याःसा–3– 1515 /दस–2008–308–97
लखनऊ : दिनॉक : 8 दिसम्बर, 2008

कार्यालय – ज्ञाप

विषय :– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण / पुनरीक्षण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्तत / मृत सभी सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों के अभिवनीकरण/ पुनरीक्षण के संबंध में निम्न आदेश प्रदान किए है।

2– यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश लिब्लराइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 तथा शासनादेश संख्या – सा–3–969 / दस–933 / 85, दिनॉक 08–08–1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग क अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3–इन आदेशों के अन्तर्गत

(क)–"वर्तमान पेंशनर " अथवा " पारिवारिक पेंशनर " का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनॉक 31–12–2005 को राज्य सरकार के नियमो के अन्तर्गत पेंशन / पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन / पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख)–"वर्तमान पेंशन " का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो 31–12–2005 को देय थी, से है। पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशन सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर –2 में किया गया है।

(ग)– "वर्तमान पारिवारिक पेंशन " का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो

—2/–

Scanned with OKEN Scanner

नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन शासनादेश संख्या – सा–3–657/दस–900/78, दिनॉक 10–05–1978 अथवा शासनादेश संख्या – सा–3–1563/दस–921/81, दिनॉक 03–11–1981 में उल्लिखित दरों पर, दिनॉक 31–12–95 को अथवा शासनादेश संख्या – सा–3–969/दस–923/85, दिनॉक 08–08–1986 से विनियिमित पारिवारिक पेंशनरों को दिनॉक 31–12–05 को अनुमन्य थी।

4–(1)

ऐसे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व से पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है, का समेकन दिनॉक 01–01–2006 से निम्नलिखित धनराशियों को सम्मिलित करके किया जायेगा :–

(I)– वर्तमान पेंशन / पारिवारिक पेंशन,

(II)–महॅगाई पेंशन जहॉ अनुमन्य हो,

(III)– वर्तमान महॅगाई राहत जैसा कि औसत AICPI536 (वर्ष 1982–100 के आधार पर) मूल पेंशन / मूल पारिवारिक पेंशन तथा महॅगाई पेंशन के 24 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य हैं शासनादेश संख्या –सा–3–1746/दस–2005–308/2004, दिनॉक 02 दिसम्बर, 2005 के अनुसार महॅगाई राहत के 50 प्रतिशत के बराबर धनराशि को महॅगाई पेंशन में परिवर्तित करते हुए,

(IV)–पेंशन / पारिवारिक पेंशन के 40 प्रतिशत के फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि भी सम्मिलित होगी।

जिन प्रकरणों में वर्तमान पेंशन की धनराशि में 50 प्रतिशत की महॅगाई राहत की धनराशि सम्मिलित है उन प्रकरणों में फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर अर्थात् महॅगाई पेंशन की धनराशि घटाकर की जाएगी।

इस प्रकार आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन को दिनॉक 01–01–2006 से मूल पेंशन माना जाएगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहॉ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहॉ यह धनराशि अनुपातिक रूप में कम कर दी जाएगी किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनॉक 01–01–2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

4–(2)

क्योंकि उपरोक्त प्रकार आगणित पेंशन की धनराशि में पेंशन के राशिकरण का अंश भी सम्मिलित है, इसलिए मासिक भुगतान में उक्त अंश को घटा दिया जाएगा।

–3/–

4–(3)

पेंशन / पारिवारिक पेंशन की दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व न्यूनतम /अधिकतम सीमा कमशः रूपया 1275 एवं रू0 13000 थी, दिनॉक 01–01–2006 से रूपया 3500 तथा 40,000 हो जाएगी।

4–(4)

वृद्ध पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की पेशंन / पारिवारिक पेंशनरों की धनराशि में निम्न प्रकार वृद्धि की जाएगी :–

पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन / पारिवारिक पेशंन की धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 20%
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक का 30 प्रतिशत
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक की धनराशि का 40 प्रतिशत
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन /पारिवारिक पेंशन का 50% प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 100% प्रतिमाह

पेंशन भुगतानादेश में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से दर्शायी जाएगी। उदाहरणार्थ यदि पेशंनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/– है, उस दशा में उसके सम्मुख रू0 2000/– प्रतिमाह अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार से उपरोयत तालिका में दर्शायी गयी पेंशन एवं अतिरिक्त पेशंन दर्शायी जाएगी। उपरोक्त प्रकरणों में पेशंनर / पारिवारिक पेशंनरों की जन्मतिथि अवश्य अंकित की जाएगी। जिससे कि भुगतान में कठिनाई न हो।

4–(5)

वर्तमान में ऐसे पेशंनर जो दिनॉक 31–03–1985 तथा 31–12–1985 के मध्य सेवानिवृत्त हुए और जिन्हें "वयैक्तिक पेंशन" पेंशन मिल रही है, वे उसे पूर्व की भॉति प्राप्त करते रहेंगे तथा उसे पेंशन समेकन में शामिल नहीं किया जायेगा।

4–(6)

उपरोक्त प्रकार से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की धनराशि में औसत सूचकांक 536(1982=100 बेस वर्ष) के अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत सम्मिलित

–4/–

Scanned with OKEN Scanner

है, इस कारण अब उक्त सूचकांक के ऊपर बढ़ी हुयी महँगाई राहत का भुगतान अनुमन्य होगा। महँगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में आदेश अलग से निर्गत किए जा रहे है।

5— यदि समेकित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू० 3500/— प्रतिमाह से कम आती है तो उसे रू० 3500/— प्रतिमाह कर दिया जाएगा तथा इसे दिनॉक 01—01—2006 से मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन माना जायेगा। जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त है, उनकी दोनों पेंशनें अधिकतम सीमा रू० 3500 प्रतिमाह होगी।

5—(1)

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर को यदि सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अधीन भी पेंशन स्वीकृत की गयी है तो उन प्रकरणों में भी दोनों पेंशनों का योग रू० 3500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। यदि केवल अशक्तता पेंशन स्वीकृत की गयी है तो उसकी न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू० 3500 से कम नहीं होगी। जहॉ केवल अवकाश पेंशन अनुमन्य है। उक्त धनराशि केवल उन प्रकरणों में भुगतान की जाएगी जिनमें 100 प्रतिशत अशक्तता प्रमाणित है तथा यदि अशक्तता की श्रेणी कम है तो उन प्रकरणों में उसी अनुपात में पेंशन घटा दी जाएगी।

6 —सेवायोजित / पुनर्योजित पेंशनर

सेवायोजित / पुनर्योजित पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों / ...
/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों पर वर्तमान में महँगाई राहत अनुमन्य नहीं है। उनके मामलों में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु प्रकल्पित महँगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायेगा जो उन्हें उस दशा में अनुमन्य होती। यदि वे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवायोजित / पुनर्योजित नहीं हुए होते और उसी के अनुसार उनकी पेंशन का समेकन किया जायेगा। दिनॉक 01—01—2006 से उनका वेतन उपरोक्तानुसार आगणित / समेकित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारित किया जायेगा। दिनॉक 01—01—2006 के उपरान्त होने वाली वृद्धि से संबंधित महँगाई राहत उन्हें सेवायोजन / पुनर्योजन की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी।

7— सरकारी सेवक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में आमेलन पर पेंशन की व्यवस्था।

(क)— पेंशन :—

ऐसे सरकारी सेवक जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमो / स्वायत्तशासी संस्थाओं में आमेलन के उपरान्त पेंशन प्राप्त कर रहें है को भी इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पुनरीक्षित किया जायेगा। परन्तु उन प्रकरणों में पुनरीक्षित नहीं

—5/—

किया जायेगा जिनमें आमेलित कार्मिक को उसकी 100 प्रतिशत पेंशन की एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनॉक 15–12–1975 के अधीन राशिकृत भाग का पुर्नस्थापन किया जा चुका है।

(ख)–पारिवारिक पेंशन:–

ऐसे प्रकरणों में जिनमें सरकारी उपकम / स्वायत्तशासी संस्थाओं में आमेलन के उपरान्त कार्मिक की मृत्यु के फलस्वरूप पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी है, उन पारिवारिक पेंशनों का भी पुनरीक्षण किया जायेगा।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के अधीन पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की गणना करते हुए एक तालिका बनायी गयी है जो इस आदेश के साथ संलग्न है। समस्त कोषागार इस तालिका के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस संदर्भ में अलग से प्राधिकार – पत्र ज़ारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग)–भुगतान की प्रकिया:–

दिनॉक 01–01–2006 से दिनॉक 30–11–2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008–09 में 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010–11 में किया जायेगा। पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को विभिन्न वित्तीय वर्षो में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जाए। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेशंनरों पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाए।

किसी पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किए जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो के देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जाए।

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(2)–समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0,
(3)–समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0

––6/–

Scanned with OKEN Scanner

स्थानीय पेशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालयसूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ)
(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ)

संख्या – सा–3–1515(1)/दस–2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

प्रत्येक को एक प्रति

1– सचिवालय के समस्त अनुभाग। –5 प्रतियाँ–
2– सचिव, विधान सभा, परिषद,विधान भवन, लखनऊ। –5 प्रतियाँ–
3– निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ –5 प्रतियाँ–
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ –5 प्रतियाँ–
6– सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को प्रचारार्थ।

7– मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद –5 प्रतियाँ–
8– मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा, विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। –5 प्रतियाँ–
9– वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर। –5 प्रतियाँ–
10– उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ। –5 प्रतियाँ–
11– इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ। –5 प्रतियाँ–
12– मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ।

नागरिक उड्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ0प्र0 लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, महानिरीक्षक, होमगार्डस, उ0प्र0 प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल,

–7/–

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० यू० पी०—41

(लाइसेन्स के अधीन रजिस्ट्रीकृत)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 31 मार्च, 2001 ई० (चैत्र 10, 1923 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, लोनी (गाजियाबाद)

1 मार्च, 2001 ई०

सं० 134/न०पा०प०/उपनियम/2000-01--उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 (1) एवं धारा 298 (2) सूची एक के "ङ" के उपखंड "ख" में दित्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये "उपविधि" तैयार की है, उपविधि का प्रकाशन दिनांक 1 जनवरी, 2001 को 'युग करवट' साप्ताहिक समाचार पत्र (गाजियाबाद) में कराया गया है । निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति या सुझाव नगरपालिका परिषद्, लोनी (गाजियाबाद) में प्राप्त नहीं हुए हैं ।

निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई भी सुझाव या आपत्ति प्राप्त न होने के फलस्वरूप इस उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है । यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

उपविधि

1--संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ--(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, लोनी तहबाजारी उपविधि 2000 कहलायेगी ।

(2) यह सम्पूर्ण नगरपालिका परिषद, लोनी क्षेत्र में लागू होगी ।

(3) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, लोनी द्वारा प्रख्यापित किये जाने के दिनांक से लागू होगी ।

2--परिभाषायें--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में--

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ।

(2) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, लोनी से है ।

(3) "प्रशासक/अध्यक्ष" का तात्पर्य प्रशासक/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, लोनी से है ।

3--इस उपविधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति नगरपालिका से बिना स्वीकृति प्राप्त किए तथा निर्धारित शुल्क भुगतान किये पालिका सीमा के भीतर पड़ने वाली किसी भी सड़क तथा पटरी, सार्वजनिक स्थान भूमि पर कोई माल न बेचेगा, न बेचने के लिए रखेगा और न कोई दुकान, चौकी गोगटी लगायेगा और न कोई गाड़ी, ठेला, ट्रैक्टर, ट्रक अथवा जानवर खड़ा करेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन गाड़ियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा जो कि निजी प्रयोग के लिए माल उतारने या लादने के लिए खड़ी की जाये ।

(अ) विक्रय के लिए प्रदर्शित की जाने वाली चीजों के अतिरिक्त सुविधा के लिए उपयोग में लाये जाने वाला सामान या फर्नीचर भी उसमें शामिल होगा ।

Scanned with OKEN Scanner

(ब) ऐसे जानवर या वाहन पर तहबाजारी शुल्क नहीं लिया जायेगा, जो किसी दुकान के सामने माल के लादने या उतारने के लिए खड़ा किया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसान कोई माल गाड़ी या वाहन से लाता है और किसी व्यापारी को बेचता है, ऐसी दशा में व्यापारी को शुल्क देना होगा, जो दस पैसे प्रति रुपये की दर से देय होगा।

4--किसी भी ऐसे स्थान पर अस्थाई फड़ स्थल, खोमचा तख्त, मूढ़ा या सामान तौलने का कांटा लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जहां पर तंग भाग या स्थान के संकीर्ण या अवरुद्ध हो जाने की आशंका हो। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की दुकान के आगे अस्थाई फड़ स्थल खोमचा या अन्य प्रकार का ढांचा बनाने या लगाने की अनुमति नही दी जायेगी।

5--यह तहबाजारी शुल्क दैनिक रूप से नगरपालिका परिषद् लोनी के अधिकृत कर्मचारी या ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूल किया जावेगा।

6--यह तहबाजारी शुल्क पक्की सड़कों के आगे या नाला, नाली या उनके आगे लगाये जाने तख्तों आदि से भी नियमित रूप से वसूल किया जायेगा।

7--इन उपविधियों के अन्तर्गत तहबाजारी शुल्क वसूल करने वाला व्यक्ति रसीद बुक में से रसीद प्रतिपर्ण (काउण्टरफाइल सहित) भरेगा और टिकट कूपन सहित प्रत्येक शुल्कदाता का यह कर्तव्य होगा कि वह रसीद को अपने पास सुरक्षित रखे, नगरपालिका के पदाधिकारियों एवं अधिकार प्राप्त कर्मचारियों के मांगने पर जांच हेतु अविलम्ब प्रस्तुत करे ऐसा अधिकारी आवश्यक निरीक्षण करने पर कूपन अपने पास रखकर रसीद पर हस्ताक्षर कर वापस कर देगा।

8--इन उपविधियों की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली समस्त चीजों से जब तक तहबाजारी शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य माना जायेगा जब तक कि सम्बन्धित सामान एवं अस्थायी अधिपत्य वहां से हटा न लिया गया हो, ऐसे फड़ों, खोमचों तथा दुकानों के आगे रखे हुये अन्य फर्नीचर आदि के लिए भी तहबाजारी शुल्क का भुगतान करना सम्बन्धित व्यक्ति का वैधानिक कर्तव्य माना जायेगा।

9--फड़ का अर्थ किसी दुकान के समक्ष सटी सड़क से बची भूमि, नाला को पाटकर बरामदा, चबूतरा या छज्जा बना लिया हो।

10--मालिक अथवा किरायेदार को अपनी दुकान के सामने के फड़ हेतु भूमि यदि वह निजी काम में प्रयोग करेगा तो निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद तहबाजारी टिकट लेना होगा, किन्तु शुल्क देकर या बिना शुल्क दिये किसी भी व्यक्ति को बैठने न देगा, तहबाजारी टिकट देते समय दुकान के मालिक को प्राथमिकता दी जायेगी, अगर खिलाफ कानून किया हो तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी और जिसे चाहे वहां बैठने का शुल्क देकर नगरपालिका बैठा सकेगी।

11--यदि दुकानदार को दूकानों के सामने का प्रयोग कोयला, लोहा, लकड़ी, रेत रोडी, सुर्खी, मोरंग, सीमेन्ट, खाद, गडासे, पाइप, बांस, बेंच, कुर्सी, जानवर बांधना, या रेहड़ी खडा करना, तिरपाल, ट्रैक्टर खड़ा करके या छप्पर बांधकर जगह का घेराव करना आदि जैसे वस्तुओं के रखने के लिए करते हैं, और उनको प्रतिदिन नहीं हटाते हैं तो उनको उक्त दैनिक शुल्क के अतिरिक्त दस रुपये दैनिक शुल्क प्रतिदिन की दर से नगरपालिका परिषद, लोनी को देना होगा, परन्तु किसी भी दशा में ऐसी वस्तु को 2 मीटर से ऊंचा नहीं रखा जायेगा। परन्तु दुकान के आगे लगा तिरपाल या छप्पर दुकान के अनुसार ऊंचाई हो सकती है, किन्तु उसका भी शुल्क नियमानुसार देना रहेगा।

12--यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दैनिक रूप से तहबाजारी के आधार पर सार्वजनिक सम्पत्ति का उपभोग करने वाले व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में किसी प्रकार के किरायेदारी के अधिकार प्राप्त न होंगे।

13--यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तहबाजारी के आधार पर सार्वजनिक सम्पत्ति का प्रयोग करने वाले उक्त सम्पत्ति पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा, इसमें खोका, जानवरों, टेन्ट के घेराव भी सम्मिलित हैं। खेल, तमाशा आदि सर्कस, ड्रामा, नौटंकी आदि की सूरत में अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, लोनी विशेष रूप से आज्ञा दे सकते हैं, बिना आज्ञा सार्वजनिक स्थान पर कोई सर्कस या ड्रामा या अन्य प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।

14--नगरपालिका का हक होगा कि वह तहबाजारी शुल्क को प्रतिदिन अपने कर्मचारियों से अथवा ठेकेदार द्वारा वसूल करा सकती है, यदि ठेका नीलाम होता है तो ठेके की शर्तें निकाय हित में इस प्रकार बनाई जायेंगी की कि समस्त धन प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष में ही निकाय को प्राप्त हो जाये, वसूली/बकाया, वसूली एवं दण्ड की प्रक्रिया अधिनियम के अनुसार की जाये।

15--यदि कोई व्यक्ति ठेकेदार, को तहबाजारी शुल्क अदा नहीं करता है तो पहले ठेकेदार अपराधी को नोटिस देगा, बाद नोटिस मिलने पर भी अपराधी शुल्क अदा

Scanned with OKEN Scanner

नहीं करता है तो ठेकेदार नोटिस की प्रति एवं प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष को देगा, जो अपराधी पर नियम का उल्लघन करने के कारण जुर्माना कर सकते हैं, जो रु० 1000.00 तक होगा, यदि अपराधी जुर्माना नहीं भरता है तो उसकी वसूली वारन्ट द्वारा की जायेगी ।

17--ठेकेदार व पालिका के मध्य किसी विवाद का निर्णय जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद महोदय द्वारा किया जायेगा, जिसे मानने के लिए ठेकेदार व पालिका बाध्य होंगे ।

17--रसीद बुक प्रत्येक दशा में पालिका द्वारा मूल्य लेकर उपलब्ध करा दी जायेगी और वही रसीद बुक मान्य होगी, जो पालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई हो ।

तहबाजारी दरें

		प्रतिदिन रु०
1	घोड़ा, तांगा, इक्का या रेहड़ी जो सवारियों या सामान से लदा हो, नगर पालिका की सीमा में प्रवेश करें	5.00
2	कपड़ा फरोश (फेरी वाले)	5.00
3	हलवाई खोमचे वाले	5.00
4	विलायती होजरी सामान बेचने वाले फड़ या छत पर	5.00
5	पटवा	5.00
6	सिले हुए कपड़े बेचने वाले	10.00
7	भुजी तथा बिस्कुट बेचने वाले	5.00
8	जूते बेचने वाला	10.00
9	बर्फ चना आईसक्रीम लेमन सोडा बेचने वाला	5.00
10	हर प्रकार की सब्जी प्रति डलिया टोकरा	2.00
11	हर प्रकार की सब्जी प्रति बोरा	6.00
12	हर प्रकार की सब्जी प्रति फड 4 X 4=16 वर्ग फीट	10.00
13	हाथ ठेला, खोमचा, फल वाले	10.00
14	दर्जी	5.00
15	रस्सी बान, मूत, मिट्टी के बर्तन, खिलौना	8.00
16	ईंधन, कोयला, इमारती लकड़ी, ईट, पत्थर, रेत सुर्खी, मोरंग आदि जमा करने पर प्रति 2 वर्गमीटर	4.00
17	लाउड स्पीकर का प्रयोग, घोड़ा तांगा पर प्रचार अथवा हाथ ठेला अथवा रिक्शा किसी प्रकार का वाहन	10.00
18	संगीत अथवा प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रचार के लिए उपयोग कारों पर करने के लिए	25.00
19	प्रति फड 4X4=16 वर्ग फीट से अधिक पर	20.00
20	चाय, दवाईयों, उपले, बिक्री हेतु चारा, आदि सामान कार, टैक्सी, टैम्पो, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि	20.00
21	दोना, फल, दुग्ध तथा खोया अन्य सामान हाथ से बेचने पर	10.00
22	प्रत्येक दुकानदार, जो पालिका की भूमि अपने प्रयोग में लायेगा या सामान रखेगा	20.00
23	अन्य सामान सडको पटरियों पर बेचने या प्रयोग में लाने पर	20.00
24	भैंसा, बोगी, सामान की ढुलाई किराये पर	5.00
25	सभी प्रकार का खोका (गुमटो) व ठेली	15.00
26	मेले में सभी प्रकार के ठिए	20.00
27	पालिका सीमा में अपने गोदामों में फलों के ट्रक व अन्य सामान ट्रक द्वारा उतारने पर प्रति ट्रक	200.00
28	उपरोक्त सामान छोटा वाहन प्रति ट्रक	100.00
29	उपरोक्त सामान प्रति बैल-गाड़ी डनलप	50.00

Scanned with OKEN Scanner

		रु०
30	अन्य जो इस सूची में नहीं है, इसी प्रकार से प्रतिदिन	10.00 से 20.00

प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के वास्ते 5 वर्ग फीट जमीन काम में लायेगा इससे अधिक प्रयोग में लाने पर एक रुपया प्रति वर्ग फीट निर्धारित टैक्स से अधिक नगरपालिका परिषद्, लोनी को अदा करेगा ।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद) यह आदेश देती है कि उपर्युक्त उपविधियों के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर रु० 1000.00 तक अर्थदण्ड किया जा सकता है, और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है तो रु० 25.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड दिया जा सकता है ।

उमेश प्रताप सिंह,
प्रशासक,
नगरपालिका परिषद्, लोनी,
गाजियाबाद ।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद

1 मार्च, 2001 ई०

सं० 135/न०पा० प०/उपनियम,/2000-01---यू० पी० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) सूची एक के 'ड़' के उपखंड 'ख' एवं शीर्षक 'ज' (लोक सुरक्षा और सुविधा) के उपखंड 'ख' में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपविधि तैयार की है, उपविधि का प्रकाशन दिनांक 1 जनवरी, 2001 को व युग 'करवट' साप्ताहिक समाचार-पत्र (गाजियाबाद) में कराया गया है । निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति या सुझाव नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई भी सुझाव या आपत्ति प्राप्त न होने के फलस्वरूप इस उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है । यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी :

उपविधि

1---संक्षिप्त नाम---यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर, टेलीफोन पोल, पोलर (बाक्स) केबिल, दूरदर्शन की डिस्क आदि पर शुल्क/किराया उपविधि कहलायेगी ।

2---परिभाषायें---विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर उपविधि में---

(क) उपविधि का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ।

(ख) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, लोनी से है ।

(ग) नगरपालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, लोनी से है ।

(घ) अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, लोनी के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है ।

(ङ.) शुल्क/किराया का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम की धारा 298(2) सूची एक के 'ड़' के उपखंड 'ख' एवं शीर्षक 'ज' के उपखंड 'ख' में निर्धारित किये जाने वाले शुल्क/किराया से है ।

3---यह उपविधि लोक सुरक्षा और सुविधा उपविधि नगरपालिका परिषद, लोनी, जिला गाजियाबाद कहलायेगी ।

4---शुल्क का विवरण अधिरोपण व संग्रह---कोई भी व्यक्ति व कर्मचारी अथवा अभियन्ता, उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि० अथवा दूरसंचार निगम लि० या अन्य कोई विभाग, जिनके द्वारा नगरपालिका परिषद्, लोनी की सीमा में पूर्व में स्थापित अथवा भविष्य में स्थापित सभी विद्युत सब-स्टेशन/स्टेशनों, बिजली व टेलीफोन, दूरदर्शन की डिस्क [केबिल टी० वी०] के तारों एवं मोबाइल फोनों के खम्बों, जो नगरपालिका परिषद् में निहित सम्पत्ति में लगे हैं, लगेंगे या लगे पाये जायेंगे भले ही उनकी पूर्व में अनुमति नगरपालिका परिषद् से ले ली गई हो या नहीं ली गई हो, अथवा नगरपालिका परिषद् के मार्ग पर स्थापित किए गये हों तथा जिनके द्वारा तार फैलाकर विद्युत् कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, दूरदर्शन की डिस्क (केबिल टी०वी०) कनेक्शनों द्वारा चाहे वह घरेलू अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए हो, धन संग्रह करेगा, उसे निम्न वर्णित अनुसूची के अनुसार किराये के रूप में उन सभी पर शुल्क का अधिरोपण व संग्रह किया जायेगा :

शुल्क अनुसूची

क्र०सं०	मद	वार्षिक शुल्क
1	2	3
		रु०
1	प्रति पोल (विद्युत् प्रवाह हेतु)	1500.00 प्रतिवर्ष

1	2	3
		रु०
2	पोल न होने पर विद्युत् केबिल बिछाये जाने की दशा में	30.00 प्रतिमीटर प्रतिवर्ष
3	टेलीफोन, बिजली एवं अन्य विभाग द्वारा स्थापित पोलों पर प्रति पोल	800.00 प्रतिवर्ष
4	पोल न होने पर भूमि के भीतर केबिल बिछाये जाने की दशा में (दूरसंचार)	30.00 प्रतिमीटर प्रतिवर्ष
5	ट्रान्सफार्मर जमीन पर फाउण्डेशन बनाकर रखे गये हों	5000.00 प्रति ट्रान्सफोर्मर प्रति वर्ष
6	ट्रान्सफार्मर, छोटे आकार जो खम्भों पर स्थापित हों	3000.00 प्रति ट्रान्सफोर्मर प्रति वर्ष
7	दूरदर्शन की डिस्क (केबिल टी० वी०) के प्रयोजनार्थ उपयोग में लायी जाने वाली वायरिंग	3.00 प्रतिमीटर प्रतिवर्ष
8	मोबाइल फोन के लिए स्थापित किए जाने वाला खम्बा (निकाय क्षेत्र में चाहे व्यक्तिगत भूमि हो या सार्वजनिक भूमि)	25000.00 प्रतिवर्ष

दण्ड

यू० पी० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, लोनी यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमावली/उपविधि या उसके किसी भाग का उल्लंघन करने वाला अर्थदण्ड का भागी होगा, जो अंकन 1000.00 (एक हजार रुपया) तक हो सकता है, यदि ऐसा उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड भी दिया जायेगा, जो पहले अपराध सिद्ध होने के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दण्ड के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराध निरन्त जारी रहा तो रु० 25.00 (पच्चीस रु०) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

उमेश प्रताप सिंह,
प्रशासक,
नगरपालिका परिषद् लोनी,
गाजियाबाद।

नगर पालिका परिषद्, मैनपुरी

13 मार्च, 2001 ई०

सं० 2229/ज०पा०प०/मै०/वाणि०/नियंत्रण–2000–2001––नगर पालिका परिषद्, मैनपुरी की सीमा में वाणिज्य नियंत्रण एवं लाइसेंस शुल्क सम्बन्धी उपविधियां, जो धारा 298, नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत बनायी गयी हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत पुष्टित कर राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाता है। यह उपविधियां राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी तथा उसी तिथि से वर्तमान में प्रचलित लाइसेंस की दरें निष्प्रभावी मानी जायेंगी।

उपविधियां

1––यह उपविधियां नगर पालिका परिषद् मैनपुरी की सीमान्तर्गत वाणिज्य नियंत्रण एवं लाइसेंस शुल्क उपविधियां कहलायेंगी।

2––यह उपविधियां एवं उनमें प्रस्तावित दरों की तालिका सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेंगी।

3––परिभाषायें––विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में––

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है;

(ख) "नगरपालिका परिषद" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् मैनपुरी से है;

(ग) "शुल्क" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद में वर्णित मदों पर लगाये गये शुल्क से है;

(घ) "प्रशासक, प्रभारी अधिकारी, अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य प्रशासक, प्रभारी अधिकारी अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् मैनपुरी से है;

(ङ) "निरीक्षणकर्त्ता" का तात्पर्य कर एवं राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक या जिनको नगर पालिका परिषद्, मैनपुरी द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाये।

4––उपविधि में दी गयी तालिका में वर्णित मदों में निर्धारित धनराशि को नगर पालिका परिषद्

मैनपुरी की सीमा में व्यापार करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों से वार्षिक शुल्क के रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देय होगा ।

5—लाइसेंस शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगा ।

(अ) आरोपित शुल्क सूचना प्रथम बार नगर पालिका परिषद् कार्यालय द्वारा शुल्कदाता के पास भेजी जायेगी, इसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित धनराशि (शुल्क) को पालिका कोष में जमा करने का दायित्व शुल्क दाता का होगा ।

(ब) यदि कोई शुल्कदाता अपना व्यापार, व्यवसाय, नगरपालिका परिषद्, मैनपुरी की सीमा में बन्द करना या हटाना चाहेगा, तो उसका दायित्व होगा कि वह व्यापार बन्द करने या हटाने के एक सप्ताह के अन्दर अपनी लिखित सूचना नगर पालिका परिषद् मैनपुरी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।

(स) इस उपविधि के प्रस्तर–5 (अ) के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को अधिशासी अधिकारी द्वारा भली–भांति जांच कराकर अपनी पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मांग समाप्त करने का अधिकार उनको होगा ।

6—शुल्क दाता को उक्त शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल, मई में जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट देय होगी । मूल कालावधि के पश्चात् शुल्क की अदायगी न किए जाने की स्थिति में शुल्क दाता को निर्धारित दर के साथ–साथ पांच प्रतिशत की अभिभार (सरचार्ज) के रूप में भी देय होगा । मास दिसम्बर तक शुल्क की अदायगी न किए जाने की स्थिति में इस शुल्क की वसूलयावी भू–राजस्व के अवशेषों की भांति भी की जायेगी, जिसका भार शुल्क दाता को वाहन करना पड़ेगा ।

7—लाइसेन्स, अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी जिसका स्तर (पद) निरीक्षक श्रेणी से निम्न न हो, द्वारा जारी किया जायेगा :

क्र० सं०	मद का नाम	शासनादेश दिनांक 27 अक्तूबर, 1994 द्वारा निर्धारित दर
1	2	3
	होटल रेस्टोरेन्ट—	रु०
1	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस (10 शैय्या तक)	1,000.00
2	तीन सितारा होटल	9,000.00
3	पांच सितारा होटल	12,000.00
	नर्सिंग होम—	
4	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	2,000.00
5	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर) रु० 50.00 प्रति बेड	5,000.00
6	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	4,000.00
7	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
8	प्राइवेट अस्पताल	5000.00
9	पैथोलाजी सेन्टर	1000.00
10	एक्सरे क्लीनिक	2000.00
11	डेन्टल क्लीनिक	2000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	1000.00
	परिवहन—	
13	आटो रिक्शा 2 सीटर	360.00
14	आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	720.00
15	आटो रिक्शा 4 सीटर	500.00
16	मिनी बस	1500.00
17	बस	2500.00
18	तांगा	50.00
19	रिक्शा किराये पर	150.00
20	रिक्शा (निजी चालित)	75.00
21	ठेला/ठेली	100.00
22	हाथ ठेला	25.00
23	बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी	25.00
24	ट्राली	150.00
25	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	1000.00
	अन्य व्यवसाय—	
26	धुलाई गृह (लान्ड्री)	500.00
27	ड्राई क्लीनर	1000.00
28	फाइनेन्स कम्पनी/चिट फंड	6000.00
29	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	12000.00

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3
		रु0
30	फाउन्डिंग, इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रियल	1200.00
31	पशुबध (स्लाटर हाउस)	10.00 प्रति पशु
32	हड्डी खाल गोदाम	1000.00
33	बार/बियर	6000.00
34	आइस फैक्ट्री	100.00
35	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5000.00
36	देशी शराब (प्रति दुकान)	6000.00
37	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	12000.00
38	भैंसा मांस की दुकान	300.00
39	बकरा मांस की दुकान	600.00
	पशुपालन--	
40	प्रति पशु	10.00
41	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	350.00
42	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरी आदि)	10.00
43	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	25.00

दण्ड

उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पालिका परिषद यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर रु0 1000.00 (एक हजार रु0) तक जुर्माना किया जा सकता है, यदि उल्लंघन निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा जो कि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि अपराध करते रहना सिद्ध हो रु0 25.00 (पच्चीस रुपया) तक हो सकता है।

महेश चन्द्र वर्मा,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मैनपुरी।

कार्यालय नगर पंचायत अम्बेहटा, जनपद सहारनपुर

12 फरवरी, 2001 ई0

सं0 मीमो/उपनियम-तहबाजारी/2000-2001--नगर पंचायत, अम्बेहटा जिला सहारनपुर द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत पूर्व में जारी तहबाजारी फीस वसूली उपनियमावली के स्थान पर नई तहबाजारी फीस उप नियमावली बनायी है। जिस पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त नगर पंचायत, अम्बेहटा द्वारा अन्तिम रूप से अपने प्रस्ताव संख्या 3 (क) दिनांक 12 अगस्त, 1999 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अन्तिम रूप से स्वीकृत तहबाजारी उप नियमावली नगर पंचायत, अम्बेहटा जिला सहारनपुर को इस गजट में प्रकाशित किया जाता है।

तहबाजारी उपनियम

संक्षिप्त नाम--(क) यह फीस नगर पंचायत, अम्बेहटा (सहारनपुर) "तहबाजारी फीस उप नियमावली" कहलायेगी।

(ख) यह फीस नगर पंचायत अम्बेहटा (सहारनपुर) की सीमा में लागू होगी।

(ग) नगरपालिका अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम; 1916 से है।

(घ) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत, अम्बेहटा जनपद सहारनपुर से है।

(च) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, अम्बेहटा से है।

परिभाषा--तहबाजारी का अर्थ उस शुल्क से है, जो नगरपालिका या नगर पंचायत की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित सार्वजनिक सड़कों, गलियों तथा खुले स्थानों व नालों का अस्थायी उपयोग करने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति (उपभोक्ता) नगर पंचायत अम्बेहटा को देगा।

1--कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत अम्बेहटा की सीमाओं के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर तहबाजारी शुल्क का भुगतान किये बिना सार्वजनिक मार्गों पर जिसमें मोटर मार्ग भी सम्मिलित हैं, एवं गलियों, बाजारों, खुले स्थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामान विक्रय हेतु फेरी लगाकर सामान बेचना, मजमा लगाना, दस्तकारी का काम करना, सिनेमा या ड्रामा दिखाना या ऐसे ही अन्य उद्देश्य से प्रदर्शन करने के लिय किसी भी प्रकार से पशु, फर्नीचर बाक्स, बैंच कुर्सी, तख्त, मूढ़ा, आदि नहीं रख सकता, जब तक कि उसने निर्धारित दरों पर नगर पंचायत को तहबाजारी शुल्क अदा कर रसीद प्राप्त न कर ली हो।

नोट--(अ) विक्रय के लिए प्रदर्शित की जाने वाली चीजों के अतिरिक्त सुविधा के लिए उपयोग में लाये जाने वाला सामान या फर्नीचर भी इसमें शामिल होगा।

(ब) ऐसी गाड़ी, जानवर या वाहन पर तहबाजारी शुल्क नहीं लिया जायेगा जो किसी दुकान या भवन के

सामने माल के लादने या उतारने के लिए खड़ा किया गया हो प्रतिबन्ध यह है कि किसान यदि कोई माल गाड़ी में लता है और उसे किसी व्यापारी को बेचता है और फिर व्यापारी इसे भूमि पर रखकर बेचता है, ऐसी दशा में किसान व व्यापारी दोनों को तहबाजारी शुल्क देना पड़ेगा।

2--किसी भी ऐसे स्थान पर अस्थायी फड़, स्टाल, खोमचा, तख्त, मूढ़ा, या सामान को तोलने का कांटा लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जहां पर तंग मार्ग अथवा संकीर्ण हो। या ऐसी अनुमति के लिए जाने से सम्बन्धित जन मार्ग अथवा स्थान के संकीर्ण एवं अवरुद्ध हो जाने की आशंका हो। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को दुकान के आगे अस्थायी फड़, खोमचा, स्थल या अन्य प्रकार का ढांचा बनाने या लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3--यह तहबाजारी शुल्क दैनिक रूप में नगर पंचायत, अम्बेहटा के अधिकार प्राप्त कर्मचारी द्वारा या ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूल किया जायेगा।

4--यह तहबाजारी शुल्क पक्की सफील के आगे या नाली-नाले या उनसे आगे लगाये जाने वाले तख्तों, बेंचों आदि से भी नियमित रूप से वसूल किया जायेगा।

5--इन उपनियमों के अन्तर्गत तहबाजारी शुल्क वसूल करने वाला व्यक्ति उपनियमावली के साथ दिये गये नमूने की रसीद बुक में से रसीद प्रतिपर्ण (काउन्टरफाइल) सहित भरेगा और टिकट कूपन सहित शुल्क देने वाले व्यक्ति को देगा जो तहबाजारी शुल्क के क्रम में दी गयी हो, रसीद केवल उसी दिन के लिये होगी जिस दिन के लिये वह दी गयी हो। शुल्क भुगतान कर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह रसीद को अपने पास सुरक्षित रखें। नगर पंचायत के पदाधिकारियों एवं अधिकार प्राप्त कर्मचारियों के मांगने पर जांच हेतु अविलम्ब प्रस्तुत करें, ऐसा अधिकारी आवश्यक निरीक्षण करने पर कूपन की प्रतिपर्ण से तुलना करने हेतु अपने पास रखकर, रसीद पर हस्ताक्षर कर वापस देगा।

6--इस उपनियम की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली समस्त चीजों से तब तक तहबाजारी शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य माना जायेगा जब तक कि सम्बन्धित सामान अथवा अस्थायी अधिष्ठान वहां से हटा न लिया गया हो ऐसे फड़ो, खोमचों तथा बन्द दुकान के आगे रखे हुए अन्य फर्नीचर आदि के लिए भी तहबाजारी शुल्क का भुगतान करना सम्बन्धित व्यक्ति का वैधानिक कर्तव्य माना जायेगा।

7--फड़ का अर्थ किसी दुकान के समक्ष यदि सड़क से बनी कच्ची भूमि या नाली को पाटकर बना चबूतरा है, बन्द दुकानदार अपनी दुकान के सामने फड़ पर सामान लगाता है तो उसको अनिवार्य होगा कि सड़क के बीच में मनुष्यों को चलने के लिए 3 मीटर स्थान छोड़ दें। इस भूमि के लिये भी शर्त या दर पर कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी।

8--मालिक अथवा दुकानदार को अपनी दुकान के सामने की फड़ हेतु यदि वह अपने निजी काम में उपयोग करेगा तो निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद तहबाजारी टिकट लेना होगा, किन्तु वह शुल्क देकर अथवा बिना शुल्क दिये किसी भी व्यक्ति को वहां बैठने न देगा तहबाजारी टिकट देते समय दुकान के मालिक को प्राथमिकता दी जायेगी अगर खिलाफ कानून किया तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी और जिसे चाहे वहां बैठने का शुल्क लेकर नगर पंचायत बिठा देगी।

9--यदि दुकान का मालिक या किरायेदार किसी महीने की 10वीं तारीख तक ऊपर के उपनियमों में निर्दिष्ट तहबाजारी टिकट नहीं लेता है तो बोर्ड के आदेश के बिना उक्त पत्रक (टिकट) उसको न दिया जायेगा, ऐसी दशा में नगर पंचायत उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगा।

10--वे दुकानदार जो अपनी दुकानों के सामने का प्रयोग कोयला, लोहा, लकड़ी, रेत, बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट, खाद, गन्डासे, पाइप, बांस, कुर्सी, बेंच, जानवर बांधना या रेडी खड़ी करना तिरपाल बांध कर जगह का घेराव करना आदि जैसी वस्तुओं के रखने के लिए करते हैं और उसको प्रति दिन हटाते नहीं उसको 4.00 रुपया प्रति दिन की दर से अतिरिक्त नगर पंचायत को देना होगा, परन्तु किसी भी अवस्था में ऐसी वस्तुओं को 1 मीटर से ऊंचा नहीं रखा जायेगा।

11--प्रमुख मेलों या त्योहारों के अवसर पर धारा 293 से अधीन अध्यक्ष अथवा ई० ओ० खास स्थान नियुक्त कर सकते हैं और नीलाम अथवा समझौते द्वारा स्थलों का शुल्क निर्धारित कर सकते हैं अथवा नीलाम या समझौते के अभाव में शुल्क की दरों की संलग्न वृद्धि की दूनी दरों से शुल्क लगा सकते हैं।

12--यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दैनिक रूप में यदि तहबाजारी के आधार पर सार्वजनिक सम्पत्ति का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में किसी प्रकार के किरायेदार के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

13--यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तहबाजारी के आधार पर सार्वजनिक सम्पत्ति का उपयोग करने वाले व्यक्ति उक्त सम्पत्ति का कोई जाफरी टेंट घेराव भी सम्मिलित है

Scanned with OKEN Scanner

खेल तमाशों आदि जैसे सर्कस ड्रामा, नौटंकी आदि की सूरत में अध्यक्ष नगर पंचायत विशेष रूप से आज्ञा दे सकते हैं ।

14—नगर पंचायत को हक हासिल होगा कि वह शुल्क तहबाजारी अमानी वा ठेके की सूरत में जैसा मुनासिब समझे वसूल करायें यदि ठेका नीलाम किया जावे तो निम्नलिखित शर्तों का पालन करे :

(अ) नीलाम से पहले नगर पंचायत में ढोल द्वारा तथा जिले की सभी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों को मुश्तहरी के अन्दर पोस्टल सर्टिफिकेट पत्र लिख दें जो नीलाम से एक सप्ताह पूर्व होगा।

(ब) जब पंचायत ठेका देगी तो बोली बोलके नालों में से आखिरी बोली (उच्चतम) देने वालों को ठेका दे दिया जावेगा, लेकिन पंचायत को यह अधिकार होगा कि यदि उसे यह ज्ञात हो जाये कि ठेकेदार मिलकर बोली दे रहा है तो वह नीलाम रद्द कर सकती है तथा नीलाम से 4 दिन के अन्दर यदि 10 प्रतिशत अधिक बोली आ जाती है तो पंचायत नीलाम की सबसे ऊंची बोली को रद्द करके 10 प्रतिशत अधिक बोली वाले को बिना किसी मुश्तहरी के स्वीकार कर लेगी।

(स) ठेकेदारान निम्न शर्तों के मानने के पाबन्द होंगे ।

[1] वह 10 प्रतिशत जर जमानत, डाकखाने में दाखिल करेगा जो ठेका समाप्त होने के तीन सप्ताह बाद वापस लेगा ।

[2] इकरारनामा शरायत लिखकर नगर पंचायत को देगा ।

(द) ठेकेदार के खिलाफ लिखित शिकायत आने पर तथा शिकायत द्वारा उसे पंचायत में सिद्ध कर देने पर कमेटी ठेकेदार का ठेका रद्द कर सकती है । जमानत जब्त कर सकती है ।

(य) ठेका प्रतिवर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए नीलाम किया जायेगा तथा ठेकेदार रकम चार किस्तों में अदा करेगा, जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को पेशगी किस्त अदा करेगा यदि निश्चित दिनांक को ठेकेदार किस्त अदा नहीं करता तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि तह वसूली रोक दें इसमें यथा समय संशोधन भी किया जा सकेगा ।

(र) यदि कोई व्यक्ति ठेकेदार को तहबाजारी शुल्क अदा नहीं करता तो ठेकेदार को भी अध्यक्ष की ओर से अपराधी को नोटिस देने का हक होगा, यदि नोटिस मिलने पर अपराधी फिर भी शुल्क अदा नहीं करता है या नोटिस लेने से इंकार करता है तो अध्यक्ष को चालान करने का अधिकार प्राप्त होगा, उसकी अलग से पंचायत में अलग से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(ल) उपनियम 12 में वर्णित अतिरिक्त कर से जुर्माना तथा सरकारी भूमि पर पंचायत के द्वारा बनाकर दी गई दुकानों के किराये से ठेकेदार को प्राप्त करने का अधिकार न होगा तथा आम रास्तों सड़क या गली कूचों या आम जगहों पर जो खड़े या चबूतरे नगर पंचायत ने ठेका या पट्टों पर दें रखे है, उनसे ठेकेदार को तहबाजारी वसूलने का अधिकार प्राप्त न होगा।

(व) ठेके की रकम ठेकेदार से वसूलयाबी नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय 6 में विहित रीति से किया जायेगा ।

(ग) नगर पंचायत के ई०ओ० , लिपिक निरीक्षण करेगें जो कि उक्त नियमों के उल्लघंन की सूचना को अध्यक्ष को देगें ।

15—तहबाजारी शुल्क निम्न दरों से वसूल किया जायेगा :

(अ) नीचे धरती पर बैठने वालों से 3.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर ।

(ब) वाहन आदि—

(2) ट्रक या ट्रैक्टर या कार अन्य 10.00 रुपये प्रतिदिन चालित वाहन ।

(3) पशुचालित वाहन बोगी बैलगाड़ी आदि 5.00 रु० प्रतिदिन ।

(4) मानव द्वारा वाहन रेडी रिक्शा आदि 5.00 रुपया प्रतिदिन (50 किलोग्राम वजन तक)

(5) मानव द्वारा वाहन रिक्शा आदि 5.00 रुपया प्रतिदिन (50 किलोग्राम से अधिक वजन तक)

(6) साईकिल 3.00 रुपया प्रतिदिन ।

(7) प्रति सिर बोझ 2.00 रु० प्रतिदिन ।

(8) बहगी खोमचा 3.00 रु० प्रतिदिन ।

(9) फेरी सिर या कंधा 2.00 रुपये प्रतिदिन ।

(10) लकड़ी बैलगाड़ी पर 5.00 रु० प्रतिदिन ।

(11) लकड़ी ट्रक ट्रैक्टर पर 10.00 रु० प्रतिदिन ।

(12) अन्य सभी जो ऊपर वर्णित न हो 5.00 रुपया प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर ।

Scanned with OKEN Scanner

विशेष

घास (चारा) के विक्रेता छूट न होंगे ।

दण्ड

यू० पी० म्युनिसिपैलिटिज ऐक्ट की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर नगर पंचायत अम्बेहटा यह निश्चय करती है कि इस उपनियम के किसी भी धारा का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा और ऐसा अपराध सिद्ध होने पर 1000.00 रुपया (एक हजार रुपया मात्र) तक अर्थ दण्ड लिया जा सकता है । अपराध जारी रहने की दशा में ऐसा उल्लंघन अतिरिक्त अर्थ दण्ड से देय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसने अपराध करना जारी रखा है, 5.00 रुपया (पांच रुपया) प्रतिदिन तक हो सकता है ।

राजकुमार खुराना,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत अम्बेहटा,
(सहारनपुर)

आगरा नगर निगम, आगरा

12 मार्च, 2001 ई०

सं० 201/डी० आई० ए० ओ०–2001—आगरा नगर निगम कर्मचारी निवृति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) विनियम, 1962 में आवश्यक संशोधन 13 नवम्बर, 1999 के बजट में प्रकाशित हुये थे, में नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 548 (1) (च) के अन्तर्गत निम्न संशोधन अन्य विनियमों के यथावत् रहते हुये प्रकाशित किए जाते हैं :

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
6—(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो पेन्शन योग्य दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने पर अथवा सेवा में रहते हुये अथवा सेवा निवृति के बाद मृत्यु हो जाने की दशा में विधवा पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो या उसके न होने पर नाबालिग बच्चों को 25 वर्ष की आयु/जीवकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक अथवा पुत्री के मामलों में विवाह होने अथवा जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने तक तथा विधवा पत्नी को आजीवन पारिवारिक पेन्शन देय होगी जो पुनर्विवाह करने पर समाप्त हो जायेगी ।	6—(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो पेन्शन योग्य दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे उन्हें सेवा निवृति पेंशन देय होगी अथवा जो कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृति के बाद मृत्यु हो जाने की दशा में अथवा एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण हो जाने के बाद सेवारत रहते हुये मृत्यु हो जाने की दशा में विधवा पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो या उसके न होने पर नाबालिग बच्चों को 25 वर्ष की आयु/जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक अथवा पुत्री के मामलों में विवाह होने पर अथवा जीवकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने तक तथा विधवा पत्नी अथवा पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन देय होगी जो पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, के पुनर्विवाह करने पर समाप्त हो जायेगी ।

उपरोक्त संशोधन पूर्व में किये गये संशोधन तिथि 1 नवम्बर, 1995 से प्रभावी समझे जावेंगे ।

उपरोक्त संशोधन नगर निगम के 30वें अधिवेशन की बैठक दिनांक 24 अक्तूबर, 2000 के प्रस्ताव संख्या 2 (13) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया ।

ह० (अस्पष्ट),
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, आगरा ।

Scanned with OKEN Scanner

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD.
[LUCKNOW BENCH, LUCKNOW]
Company Petition no. 57 of 1999
ORIGINAL JURISDICTION
In the matter of the Companies Act, 1956

R. K. Singh .. *Petitioner*

Versus

M/s. Encore Constructions Pvt. Ltd., at its registered Office 120, Nilgiri Complex, Indira Nagar, Lucknow.

.. *Opp. Party.*

Advertisement of Petition

Notice is hereby given that a petition for a winding up of the above named company by the High Court at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow was on the 20th day of December 1999, presented to the said Court by the said company and that the said petition is directed to be heard before the Court on the 23rd day of April, 2001.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Courts and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Advocate for the petitioner—
Jaideep Narain Mathur
A-1, Sapru Marg, Lucknow.
Dated March 26, 2001

(Sd) ILLEGIBLE,
Deputy Registrar.

ORDER

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD

[LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.]

Company Petition no. 57 of 1999 (CP)

Petition for winding up under sections 433 (e) and 434 of the Companies Act, 1956.

R. K. Singh son of Sri S. N. Singh, resident of 16/1434, Indira Nagar, Lucknow. .. *Petitioner*

Versus

Encore Constructions (P) Limited with its Office at 120, Nilgiri Complex, Indira Nagar, Lucknow. .. *Respondent,*

Lucknow, dated March 12, 2001.

Hon'ble Ashish N. Trivedi .. *Judge.*

Learned Counsel for the petitioner prays for and is granted two weeks to take fresh steps for publication of notice of service on the Respondents and shall thereafter file Affidavit of service. The notice shall be issued fixing a date in the last week of April 2001.

ASHISH N. TRIVEDI,

DATED: March 12, 2001.

Notice

I, Rattan Singh s/o late Sri Bhag Singh, continuing partner of M/s. Namdhari Brothers, Allahabad Road, Khairabad, Sultanpur give you notice that Smt. Kiran Deep Kaur w/o Dr. Sukhdev Singh, w/o 697, Khairabad Sultanpur and Smt. Hardeep Kaur w/o Sri Raj Bahadur, Singh, r/o 697, Khairabad, Sultanpur have been admitted as partners from Ist April, 1985 in the above firm.

Dated March 28, 2001.

RATTAN SINGH

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

लखनऊ जल संस्थान लखनऊ

अधिसूचना

15 मार्च, 2001 ई०

सं० 650/रु० प्र० 2000–2001 उत्तर प्रदेश जलसंभरण व सीवर अधिनियम, 1975 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 43, 1975) की धारा 25 की उपधारा 2(vi) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लखनऊ जलसंस्थान द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत लगत पर सुविचार कर उत्तर प्रदेश जल निगम से उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 2 (8) के अन्तर्गत अनुमोदन के पश्चात न्यूनतम जल मूल्य/जल परिव्यय की दरें उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) व (2) के अधीन प्रकाशित की जाती हैं। यह दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

घरेलू उपयोग हेतु न्यूनतम जलमूल्य/जल प्रभार (दर रु० 2.00 प्रति हजार लीटर) की संशोधित दरें

क्रम सं०	जल संयोजन का आकार	कर निर्धारण रहित सम्पत्ति के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम जल मूल्य/जल प्रभार प्रति वर्ष											
		सम्पत्तियों के न्यूनतम जलमूल्य/प्रभार		रु० 360.00 तक		361 से रु० 2000		2001 से 3500 तक		3501 से 5000 तक		5001 से अधिक	
		अगस्त, 96 से लागू दरें	संशोधित दरें	अगस्त, 96 से लागू दरें	संशोधित दरें	अगस्त, 96 से लागू दरें	संशोधित दरें	अगस्त, 96 से लागू दरें	संशोधित दरें	अगस्त, 96 से लागू दरें	संशोधित दरें	अगस्त, 96 से लागू दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15 एम०एम० तथा 13 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सम्पत्तियों के लिए	480.00	588.00	360.00	441.00	480.00	588.00	720.00	882.00	960.00	1176.00	1200.00	1470.00
2	15 एम(एम० (क्रमांक 1 के अतिरिक्त)	600.00	735.00	360.00	441.00	480.00	588.00	720.00	882.00	960.00	1176.00	1200.00	1470.00
3	20 एम(एम०	1800.00	2205.00	540.00	661.50	720.00	882.00	1080.00	1323.00	1380.00	1690.50	1800.00	2205.00
4	25 एम०एम०	2400.00	2940.00	840.00	1029.00	1080.00	1323.00	1680.00	2058.00	2040.00	2499.00	2400.00	2940.00

नगर पालिका पेंशन नियम

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा 297 की उप धारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उक्त अधिनियम की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 2830?/II-3-79-217 विधि -1979 दिनांक 19 जुलाई, 1979 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास अनुभाग-6 संख्या 3898/II-6-1984-217 विधि 179 दिनांक 1 अक्टूबर, 1984 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवा निवृत्त लाभ विनियमावली, 1984 बनायी गयी, जो गजट के प्रकाशन तिथि 1 जून, 1985 से प्रवृत्त हुई ।

"विनियमों का लागू होना "

यह विनियमावली, उप विनियम-(3) के अनुसार निम्नलिखित पर लागू होगी :-

(1) अकेन्द्रीयित सेवाओं के उन समस्त पदधारियों पर जो इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् पालिका द्वारा सृजित पेंशन के योग्य पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाये एवं प्रवृत्त होने के दिनांक को पालिका द्वारा सृजित पेंशन योग्य पदों पर अपनी मौलिक नियुक्ति पर हो ।

(2) अकेन्द्रीयित सेवाओं के उन समस्त पदधारियों पर जो दिनांक 1 अप्रैल 1979 को उत्तर प्रदेश पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के किसी पद पर स्थायी थे, किन्तु इस प्रयोजन के हेतु सेवा निवृत्त हो चुके हैं, बशर्ते कि वे इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर इस विनियमावली द्वारा नियंत्रित होने के लिये अपना विकल्प दें ।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास अनुभाग-6 अधिसूचना संख्या 1243/II-6-1988, लखनऊ दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 के अनुसार उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की गयी कि " 15 दिसम्बर, 1988 को या इससे पूर्व इस विनियमावली द्वारा नियंत्रित होने के लिये अपना विकल्प दें दिया हो" ।

नोट:- जो 1 जून, 1985 या उसके पश्चात सेवा निवृत्त होंगे उन पर यह नियमावली स्वतः लागू होगी ।

कु० प्र० उ०

पेंशन की पात्रता

§1§ यदि किसी पदधारी ने अपने भविष्य निधि लेखा में जमा पालिका के अंशदान एवं बोनस की धनराशि का अन्ततः आहरण कर लिया हो तो उसे वह धनराशि ब्याज सहित पेंशन निधि में जमा करनी होगी ।

§2§ यदि किसी पालिका ने पदधारी की भविष्य निधि में बोनस के अपना अंशदान जमा न किया हो तो नगर पालिका बोर्ड को पेंशन निधि में प्रत्येक ऐसी धनराशि ब्याज सहित जमा करनी होगी ।

3- सम्बद्ध कर्मचारी के भविष्य निधि लेखा में जमा किये गये पालिका के अंशदान और बोनस की धनराशि का भविष्य निधि लेखा से आहरण किया जायेगा और उसे नगर पालिका बोर्ड द्वारा पेंशन निधि में जमा किया जायेगा ।

यदि उक्त शर्तें पूरी न होती हो तो पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी को अपने इस विवेक का प्रयोग करने की शक्ति होगी कि यह विनियमावली अकेन्द्रीयित सेवाओं के लिये किसी विशिष्ट पदधारी पर लागू न हो ।

परन्तु इस विनियमावली द्वारा नियंत्रित पदधारी उन पर इस विनियमावली के लागू होने के दिनांक से नगर पालिका बोर्ड द्वारा उनकी भविष्य निधि में देय बोनस और अंशदान के लाभ को समपहृत कर देंगे ।

पेंशन और उपदान की गणना

विनियमावली के विनियम-4 के अन्तर्गत अधिवर्षता सेवा निवृत्ति, अक्षम और प्रति कर पेंशन 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर सेवा निवृत्त कर्मचारी पूरी पेंशन पाने का हकदार हो जाता है अर्थात औसत परिलब्धियों के 33/90 के अनुसार से पेंशन अनुमन्य होगी । यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक है किन्तु 33 वर्ष से कम है तो आनुपातिक पेंशन दी जायेगी । $\frac{33}{80} = \frac{\text{अर्हकारी सेवा की पूर्ण छमाही}}{80 \times 2}$

$= \frac{1}{160}$ अर्थात अर्हकारी सेवा की पूर्ण छमाही अवधि गुणे औसत परिलब्धियों का 1/160 की धनराशि देय होगी, तथा उपदान की धनराशि का भुगतान विनियम-5 के उप विनियम §1§§3§ एवं §4§ के अनुसार अनुमन्य होगी ।

कृ० प० उ०

(1) कोई अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(2) पद "अल्प और प्रतिकर पेंशन का वही अर्थ होगा, जो उसके लिए सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स में है " ।

मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की गणना

(1) किसी पदधारी की सेवा निवृत्त होने पर उपदान जिसकी धनराशि परिलब्धियों में अर्हकारी सेवा की पूर्ण छमाही अवधि की कुल संख्या से गुणा करने पर जो धनराशि हो, उसके एक चौथाई के बराबर धनराशि होगी, किन्तु परिलब्धियों की अधिकतम साढ़े सोलह गुना से अधिक न होगी ।

" नगर पालिका बोर्ड के पदधारियों की परिलब्धियों में समय-समय पर स्वीकृत मंहागई भत्ता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ता होगा " ।

(2) यदि पालिका /बोर्ड की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाय तो उपदान का भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिसे या जिन्हें विनियम-6 के उप नियम (1) से (8) के अधीन नाम- निर्देशक द्वारा उपदान पाने का अधिकार प्रदत्त किया जाय, किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो उसका भुगतान विनियम -6 के उपविनियम -8 में इंगित रीति से किया जायेगा जिसकी धनराशि पदधारी की परिलब्धियों के न्यूनतम बारह गुना और अधिकतम साढ़े सोलह गुना के अधीन रहते हुए, उसकी परिलब्धियों में अर्हकारी सेवा की छमाही अवधि की कुल संख्या से गुणा करने पर जो धनराशि हो उसके एक चौथाई के बराबर धनराशि होगी ।

(3) यदि किसी ऐसे पदधारी की जो इस विनियमावली के भाग-2 के अधीन पेंशन या उपदान प्राप्त करने के लिये पात्र हो गया हो या जिसने वस्तुतः उसे प्राप्त कर लिया हो, सेवा निवृत्ति के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाय और मृत्यु के समय तक उसे ऐसे उपदान या पेंशन के मद्दे अनुमन्य या वस्तुतः प्राप्त धनराशि और उपविनियम (1) के अधीन स्वीकृत उपदान और उसके द्वारा संशीकरण करायी गयी पेंशन कि किसी भाग का संराशीकृत मूल्य कुल मिलाकर उसकी परिलब्धियों की बारह गुना धनराशि से कम हो तो उप विनियम (2) में निर्विर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कम धनराशि के बराबर उपदान स्वीकृत किया जायेगा

(4) किसी भी स्थिति में उपदान की धनराशि 30,000 (तीस हजार) से अधिक न होगी ।

"विनियमावली के परिभाषित पद"

"औसत परिलब्धि"

औसत परिलब्धि का तात्पर्य ऐसी औसत परिलब्धियों से है जिन्हें पदधारी ने जिस मास सम्बद्ध पदधारी को सेवा निवृत्त होना हो विनियमावली के भाग एक के विनियम-2 उपविनियम (1) (एक) (दो) के परन्तुक के अनुसार, उसके ठीक पूर्ववर्ती दस माहों के दौरान प्राप्त किया हो ।

"परिलब्धि"

परिलब्धि का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड दो भाग दो से चार के फण्डामेंटल रूल 9 (21) में यथा परिभाषित वेतन से है । इस वेतन में मँहगाई भत्ता भी सम्मिलित होगा ।

परन्तु यदि कोई पदधारी यथास्थिति सेवा निवृत्ति या मृत्यु के समय छुट्टी पर हो तो परिलब्धि वह मान ली जायेगी जो उस समय हो तो यदि वह उस समय छुट्टी पर न होता ।

अर्हकारी सेवा :-

अर्हकारी सेवा का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो निम्नलिखित को छोड़कर समय-समय पर यथा संशोधित सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-368 के उपबन्धों के अनुसार पेंशन के लिए अर्हता प्रदान करती हो ।

(एक) सम्बद्ध नगर पालिका बोर्ड के अधीन पेंशन रहित अधिष्ठान में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि ।

(दो) किसी कार्य प्रभारित अधिष्ठान में सेवा की अवधि और

(तीन) किसी ऐसे पद पर जिसके लिये आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, सेवा की अवधि :

परन्तु सम्बद्ध के अधीन निरन्तर अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना अर्हकारी सेवा के रूप में की जायेगी उसी या किसी अन्य पद पर सेवा के किसी व्यवधान के बिना बाद में उसे स्थायी कर दिया जाय ।

टिप्पणी :-

यदि किसी पेंशन रहित अधिष्ठान कार्य प्रभारित अधिष्ठान में या आकस्मिकता निधि से भुगतान किये जाने वाले किसी पद पर की गयी सेवा किसी पेंशन योग्य अधिष्ठान में अस्थायी सेवा और स्थायी सेवा की अवधि की बीच पड़ती है

कृ० प० उ०

तो वह सेवा का व्यवधान नहीं माना जायेगा ।

सेवा निवृत्ति :-

========== सेवा निवृत्ति का तात्पर्य किसी पद धारी के अकेन्द्रीयित सेवा से अधिवर्षता पर अनिवार्यतः या स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति होने पर या स्थायी पद पर स्थायी नियुक्ति की समाप्ति पर यदि पदधारी की नियुक्ति किसी अन्य पद पर न की जाय या उसे उसके मौलिक पूर्ववर्ती मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित कराना संभव न हो, सेवा मुक्त होने से है ।

टिप्पणी :-

-------- सेवा से स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का तात्पर्य ऐसी सेवा निवृत्ति से है जो 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर लेने पर हो ।

सेवा निवृत्ति पेंशन :-

========== सेवा निवृत्ति पेंशन का तात्पर्य ऐसी पेंशन से है जो ऐसे पद धारी को स्वीकृत की जाय, जिसे अधिवर्षता की आयु प्राप्त होने के पूर्व सेवा निवृत्ति होने की अनुज्ञा की जाय और इसके अन्तर्गत ऐसी पेंशन भी है जो ऐसे पद धारी को स्वीकृत की जाय जिसे अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पूर्व सेवा निवृत्ति होने की अपेक्षा की जाय ।

अधिवर्षता पेंशन :-

========== अधिवर्षता पेंशन का तात्पर्य किसी ऐसे पदधारी को स्वीकृत पेंशन से है सुसंगत विनियमों के अधीन विशिष्ट आयु प्राप्त होने पर सेवा से निवृत्त होने का हकदार हो ।

पारिवारिक पेंशन :-

========== विनियमावली के विनियम-7 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की गयी है ।

(1) ऐसे पदधारी के जिसकी चाहे सेवा निवृत्ति के पश्चात या कम से कम 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाय, परिवार को दस वर्ष की अवधि के लिये पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है, जिसकी धनराशि अधिकतम रू0 150.00 प्रतिमाह और न्यूनतम 30 रूपये प्रतिमाह होगी ।

रू0 प0 उ0

परन्तु पारिवारिक पेंशन दिये जाने की अवधि किसी भी स्थिति में उस दिनांक से जब मृत पदधारी ने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली होती, यदि वह सेवा में होता, पाँच वर्ष से आगे नहीं बढ़ाई जायेगी ।

परन्तु यदि पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है तो उपदान का जहाँ अनुमन्य हो, दो माह की परिलब्धियों के बराबर की धनराशि अभ्यर्पित करना होगा, किन्तु अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि रू0 5000/= से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी :-

ऐसे पदधारी के परिवार को जिसकी मृत्यु बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पूर्वकिन्तु कम से कम दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् हो जाय, पारिवारिक पेंशन दिये जाने पर, पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी विचार कर सकता है । परन्तु जहाँ अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से कम हो वहाँ पारिवारिक पेंशन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी ।

पारिवारिक पेंशन की धनराशि

§18§ सेवाकाल में मृत्यु होने पर उस अधिवर्षता पेंशन की आधी होगी जो पदधारी को उस समय अनुमन्य होती यदि वह अपनी मृत्यु के दिनांक से अगले दिनांक को सेवा निवृत्त होता तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात मृत्यु होने पर सेवा निवृत्ति के समय उसे स्वीकृत पेंशन की आधी होगी ।

पारिवारिक पेंशन में संराशिकरण भाग की कमी

पारिवारिक पेंशन की धनराशि में पेंशन भोगी द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व संराशीकरण की गयी पेंशन की धनराशि यदि कोई हो, कम हो जायेगी ।

पारिवारिक पेंशन के लिये नाम निर्देशन

प्रत्येक पदधारी अपने स्थायीकरण के तुरन्त बाद प्रपत्र "ड." में नाम निर्देशन करेगा, जिसमें यह इंगित किया गया हो कि पारिवारिक पेंशन उसके परिवार के सदस्यों को किस क्रम में देय होगी और जिस सीमा तक विधि मान्य होगी, उस सीमा तक वह पेंशन ऐसे नाम निर्देशन के अनुसार देय होगी, बशर्ते सम्बद्ध नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उस दिनांक को जब उसे पेंशन देय हो जाय, विनियमों §38§ के अधीन अपात्य हो

जाय, तो पेंशन ऐसे नाम निर्देशन के क्रम में अगले निम्न व्यक्ति को स्वीकृत की जायेगी ।

§i§ क- इस भाग के अधीन प्रदत्त पेंशन मृत पदधारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को एक साथ देय न होगी ।

§ii§ ज्येष्ठतम उत्तर जीवी विधवा को, यदि मृत पदधारी पुरूष पदधारी था या पति को यदि मृत पदधारी महिला पदधारी थी ।

§iii§ उपर्युक्त के न होने पर ज्येष्ठतम उत्तर जीवी पुत्र को ।

§iv§ उपर्युक्त §iii§ और §iii§ के न होने पर ज्येष्ठतम उत्तर जीवी अविवाहिता पुत्री को और §i§ से §5§ के न होने पर ज्येष्ठतम विधवा पुत्री को ।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में पेंशन देय न होने की दशा में पेंशन निम्नलिखित को दी जा सकती है ।

ख- 1. पिता को

2. उपर्युक्त के न होने पर माता को

3. उपर्युक्त 1 और 2 के न होने पर 18 वर्ष से कम आयु के ज्येष्ठतम उत्तर जीवी भाई को ।

4. उपर्युक्त 1 से 3 के न होने पर ज्येष्ठतम उत्तर जीवी अविवाहिता बहिन को ।

5. उपर्युक्त 1 से 4 के न होने पर ज्येष्ठतम उत्तर जीवी विधवा बहिन को ।

उपर्युक्त 1 से 5 के न होने पर पूर्व मृत पुत्र के बालकों को उसी क्रम में जिस क्रम में वह खण्ड क के §iii§ और §iv§ के अधीन मृत कर्मचारी के बालकों को देय है ।

ज्येष्ठतम उत्तर जीवी विधवा

ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा का अर्थ पदधारी के साथ विवाह होने के दिनांक के अनुसार ज्येष्ठतम के निर्देश में न कि उत्तरजीवी विधवाओं की आयु के निर्देश में लगाया जाना चाहिये ।

कृ0 प0 उ0

सरांशिकरण :- पेंशन की संराशीकरण की सुविधा उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स के अनुसार सुलभ होगी, किन्तु पेंशन की अधिकतम धनराशि जिसका सरांशिकरण किया जाय, इस विनियमावली के अधीन अनुमन्य पेंशन की एक तिहाई होगी ।

परन्तु सरांशिकरण के पश्चात वस्तुतः देय पेंशन किसी भी स्थिति में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 474 और 474 एवं अधीन अनुमन्य पेंशन का कम से कम आधा या 20 रूपये जो भी अधिक हो, होगी ।

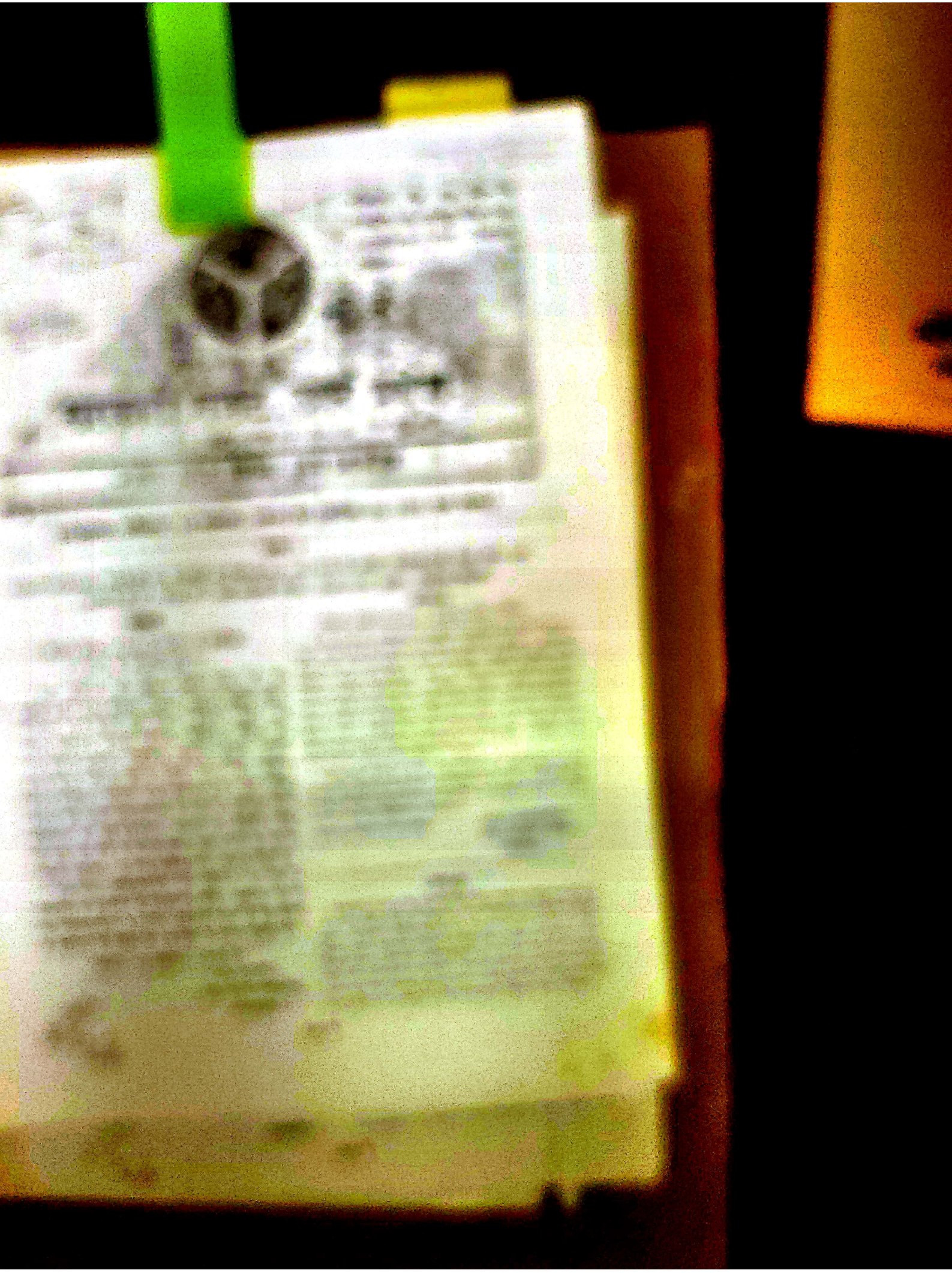
पेंशन संबंधी अंशदान :- ऐसे प्रत्येक पदधारी के लिये जो इस विनियमावली के अधीन पेंशन का हकदार हो, सम्बद्ध नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उसके वेतन के 12 प्रतिशत के बराबर आर्थिक सहायता देय होगी ।

प्रकीर्ण

(1) अकेन्द्रीयित सेवा के प्रत्येक पदधारी की सेवा निवृत्ति के दिनांक से पूर्व एक वर्ष पूर्व सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रपत्र "छ" में उनके आवेदन पत्र को पूरा करेंगे और उन्हें नगर पालिका के लेखाकार को भेजेंगे । लेखाकार पेंशन और उपदान की धनराशि की जॉच करने के पश्चात उसे अधिशासी अधिकारी के माध्यम से नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो पेंशन एवं उपदान के पत्रादि की समीक्षा करेगा । अध्यक्ष इस पत्रादि को पदधारी के सेवा निवृत्ति के छः माह पूर्व परीक्षा/निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के पास पेंशन और उपदान की धनराशि के सत्यापन और पुष्टि के लिये भेजेगा । परीक्षक, स्थानीय निधिलेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पेंशन और उपदान की धनराशि का सत्यापन और पुष्टि किये जाने के पश्चात इन पत्रादि को मण्डल, आयुक्त के पास पेंशन और उपदान की स्वीकृति और भुगतान के लिये प्रेषित किया जायेगा ।

(2) मण्डलायुक्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन और या उपदान स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा ।

------x------



Scanned with OKEN Scanner

AO
for M.P.
&
for M N A
6/1/2000

1316/MNA/1999
6/1/2000

405/210
7-2-2000

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० यू० पी०—41
(आफ्तेन्यड टू पोस्ट बिदाउट
प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

•उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 13 नवम्बर, 1999 ई० (कार्तिक 22, 1921 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण–पत्र; जन्म–मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार–भाव; सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

[नोटरी रूल्स, 1956 के नियम 6 उपनियम (2)(ए) के अन्तर्गत सूचना]

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री अनिल कुमार सक्सेना, अनवार अहमद, अतीक अहमद दामोदर प्रसाद यादव, हरी शंकर, जगदीश सिंह, जय किशन त्रिपाठी, कल्पना तिवारी, मोहम्मद हयात खां, राम स्वरूप आजाद, राजेश्वर कुमार मिश्रा, राजीव कुमार गुप्ता, रविन्द्र कुमार, राहत उल्ला खां, सन्तोष कुमार सक्सेना, सत्यपाल सिंह, साजिद अली खां; सैयद अहमद खां आदि अधिवक्ताओं नें तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में पूर्व एडवोकेट नोटरी श्री हरजीत सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुए नोटरी के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये हैं।

यदि उक्त अधिवक्ताओं को नोटरी के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सरकारी गजट में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिन के अन्दर प्रस्तुत करे।

दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 ई०

ह० (अस्पष्ट),
कृते जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत।

NOTICE

[*Under Rule* 6 (2) (*a*) *of Notary Rule*, 1956]

It is hereby notified for public information that Sarva-Sri Anil Kumar Saxena, Anwar Ahmad, Atique Ahmad, Domodar Prasad Yadav, Hari Shankar, Jagdish Singh, Jai Kishan Tirpathi, Kalpna Tivari, Mohd. Hayat Khan, Ram Swarup Azad, Rajeshwar Kumar Misra, Rajeev Kumar Gupta, Ravindra Kumar, Rahat-Ullah Khan, Santosh Kumar Saxena, Satya Pal Singh Sajid Ali Khan, Sayeed Ahmad Khan, have applied for their appointment as 'Notary' at tohsil Puranpur, district Pilibhit for the post caused by the death of late Sri Harjeet Singh.

Objection if any to the appointment of aforesaid applicants as 'Notary' should be submitted to the undersigned within fourteen days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Dated—October 13, 1999.

(Sd.) ILLEGIBLE,
For *District Judge*,
Pilibhit.

NOTICE

Notice is hereby given that Shri Ashok Kumar Kamani s/o late Hari Ram Kamani, r/o Siswabazar, Thana Kothibhar, District Mahrajganj (U. P.), one of the partner of the Firm Shri Ganesh Silicate Soda and Glass Factory, Post Siswabazar, District Mahrajganj (U. P.) and its branches, has retired and all its assets and liabilities have been taken over by the continuing partner's. They will be only entitled to realise the dues of the aforesaid Firm from 1.4.99.

Scanned with OKEN Scanner

A rotirement deed had also been executed on a stamp of Rs. 65.00 on April 1, 1999 effective from April 1, 1999.

Now our Head Office address have been changed Shri Ganesh Silicate Soda, Glass Factory, C/o Kamani Sadan, Opp. P.W.D. office, Gorakhpur and with the branch (factory) at Ushagram P.O. Asansol, Distt. Burdwan (W. B.)

ANAND MOHAN KAMANI
SURENDRA MOHAN KAMANI
SUNIL MOHAN KAMANI

FORM 120

IN THE COURT OF JUDGE INSOLVENCY, KANPUR AT KANPUR, DISTRICT KANPUR NAGAR.

Notice of creditors of the date of hearing of an Insolvency Petition].

[SECTION]

Insolvency Petition no. 3 of 1998

मे० वर्मा रोडवेज सा० 133/174 ए० ट्रान्सपोर्टनगर, कानपुर द्वारा भागीदार रमेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल वर्मा, सा० 133/174-ए०, ट्रान्सपोर्टनगर, कानपुर।

.. *Petitioner.*

vs.

1—मे० बालगोविन्द बिन्दा प्रसाद भागीदार फर्म, सा० 51/53 नयागंज, कानपुर ।

2—लखन लाल गुप्त पुत्र स्व० श्री बिन्दा प्रसाद गुप्त, सा० 24/22 कराचीखाना, कानपुर ।

3—श्रीमती उमा गुप्ता बालिग पत्नी स्व० श्री अनिल कुमार, सा० 24/22 कराचीखाना, कानपुर ।

.. *Respondents.*

Whereas petitioners have applied to thiscourt by a petition dated September 8, 1998 to be declered an Insolvent under the Provincial Insolvency Act 5 of 1920 and your name appears in the list of creditors filed by the aforesaid debtor. This is to give you notice that the court fixed November 20, 1999 for the hearing of the aforessid petition and the examination of debtor. If you desire to be represented in the matter, you should attend in person or by duly instructed pleader.

Dated—October 12, 1999.

By order,
(Sd.) ILLEGIBLE,
Judge Insolvency,
Kanpur Nagar.

FORM 120

IN THE COURT OF JUDGE INSOLVENCY, KANPUR AT KANPUR, DISTRICT KANPUR NAGAR.

[*Notice to creditors of the date of hearing of an Insolvency Petition.*]

[SECTION]

Insolvency Petition no. 1 of 1999.

श्रीमती रेखा जैन बालिग पत्नी श्री कैलाश जैन, सा० 1/8 नवशील अपार्टमेंट, 56 कैन्ट, कानपुर प्रोप्राइटर फर्म मे० मुकेश ब्रदर्स, 49/82 नौघड़ा, कानपुर ।

.. *Petitioner.*

vs.

1—मे० किशनलाल राम प्रकाश भागीदारी फर्म स्थित 51/10 रामगंज नौघड़ा, कानपुर ।

2—रामप्रकाश अग्रवाल बालिग पुत्र स्व० श्री नन्दकिशोर अग्रवाल, सा० 128/153 ब्लाक-ई, किदवई नगर ।

3—किशन लाल चावला बालिग पुत्र श्री रामलाल चावला सा० यच० 2/28 पाण्डुनगर, कानपुर ।

4—किशनलाल गुप्ता बालिग पुत्र स्व० श्री केदारनाथ गुप्ता, सा० 67/21 दौलतगंज, कानपुर ।

.. *Respondents.*

Whereas petitioners have applied to this court by a petition dated January 11, 1999 to be declared an Insolvent under the Provincial Insolvency Act 5 of 1920 and your name appears in the list of creditors filed by the aforesaid debtor. This is to give you notice that the court fixed December 13, 1999 for the hearing of the aforessid petition and the examination of debtor. If you desire to be represented in the matter, you should attend in person or by duly instructed pleader.

Dated—October 12, 1999.

By order,
(Sd.) ILLEGIBLE,
Judge Insolvency,
Kanpur Nagar.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Original Jurisdiction

In the matter of the Companies Act, 1956
AND

In the matter of Rajinder Pipes Limited, registered office at 'Rajender House, 117/H-1/303, Model Town, Pandav Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh .

Company Petition no. 95 of 1998

NOTICE OF PETITION

A petition under sections 433, 434 and 439 of the Companies Act, 1956 for winding up of Rajinder Pipes Limited, was presented by J. K. Credit and Finance Limited, 'Link House' 4th Floor, 3 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 through Sri Nimai Dass, Advocate on the 4th day of August, 1998, and the said petition is fixed for hearing before the Company Judge on the 29th day of November, 1999.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later the five days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the under signed to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Dated—October 1, 1999
Sri Nimai Dass,
Advocate,
43, Tagore Town, Allahabad,
Counsel for the petitioner.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Deputy Registrar,

नगर निगम, आगरा

संख्या 447/डी/ए० ओ०/99/जी,
दिनांक 5 मार्च, 1999 ई०

आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) विनियम, 1962, जो आवश्यक संशोधनों सहित 30 मार्च, 1995 के सरकारी गजट में प्रकाशित हुई थी, में नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 548[1 (च)] के अन्तर्गत निम्न संशोधन, अन्य विनियमों के यथावत् रहते हुए प्रकाशित किये जाते हैं--

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित संशोधन
1--(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट), 1962 कहा जायेगा ।	1--(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनीफिट) विनियम, 1962 होगा ।
	2--(2) द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि उन विनियमों में औसत परिलब्धियों की वह ही उपयुक्त परिभाषा मान्य होगी जिसे समय-समय पर राज्य सरकार अपने पेंशनरों के लिए परिभाषित करे ।
4--(2) डेथकम (रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपादान :	4--(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपादान (डेथकम-रिटायरमेन्ट) ग्रेच्युटी :
यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को, जिन्होंने उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या-5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपादान दिया जायेगा (दस वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपादान सर्विस ग्रेच्युटी देय होगी) उसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी । मृत्यु उपादान सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार की मृत्यु उपादान अनुमन्य होगा, जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का दो गुना, एक से अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम की सेवा पर परिलब्धियों का छः गुना, पांच से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के अधिक के बराबर-बराबर जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (तैंतीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा ।	यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को जिन्होंने उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या-5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपादान दिया जायेगा (दस वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपादान (सर्विस ग्रेच्युटी) देय होगी उसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी । मृत्यु उपादान सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को मृत्यु उपादान अनुमन्य होगा जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का दो गुना एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियो का छः गुना, पांच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष अथवा उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के आधे के बराबर, जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (तैंतीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 मे विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा ।
6 (2) (ख) अधिकतम रुपया 1250/-प्रतिमाह होगा । न्यूनतम धनराशि 375.00 होगी ।	6 (2) (ख) पारिवारिक सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) की अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिमाह वह धनराशि होगी जो राज्य सरकार अपने पारिवारिक पेंशनरों के लिए समय-समय पर निर्धारित करे ।

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित संशोधन
प्रतिबन्ध यह भी है कि पारिवारिक सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) की न्यूनतम धनराशि से सम्बन्धित अधिकारी को उसको सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत होने वाले सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) की धनराशि से अधिक न होगी, अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाये तो सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) उस धनराशि से अधिक न होगी जो उसे मृत्यु के बाद वाले दिन सेवानिवृत्त होने पर निवृत्ति वेतन के समय में प्राप्त होता ।	यह प्रतिबन्ध निरस्त किया जाता है जो दिनांक 1 नवम्बर, 1995 से प्रभावी होगा ।
7--(1) (त) निरस्त किया जाता है ।	7--(1) (त) नगर निगम के समस्त सेवानिवृत्ति/पारिवारिक पेंशनरों को राजकीय पेंशनरों की भांति राजाज्ञा सा-4-1120/दस-301-87, दिनांक 28 जुलाई, 1987 के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन को दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनः निर्धारित कर उस पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय पेंशनरों को दिये जाने वाले महंगाई राहत व अन्य लाभ दिये जायें । 1 जनवरी, 1986 से 29 फरवरी, 1988 तक सेवानिवृत्त को राज्य सरकार द्वारा राजकीय पेंशनरों को दिये जाने वाले समस्त महंगाई राहत व अन्य लाभ अनुमन्य होंगे ।
9--प्रतिबन्ध यह है कि संराशिकरण के बाद देय सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) की धनराशि किसी भी दशा में सिविल सर्विस रेगुलेशन के अन्तर्नियम 474 तथा 474-ए के अन्तर्गत निकलने वाले सेवानिवृत्त वेतन (पेंशन) के आधे अथवा 50 रुपया से, जो भी अधिक हो, कम न होगी ।	9--प्रतिबन्ध यह है कि संराशिकरण के बाद देय पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में सिविल सर्विस रेगुलेशन के अन्तर्नियम 474 व 474-ए के अन्तर्गत कैलकुलेटिड पेंशन के आधे से कम न होगी । प्रतिबन्ध यह भी है कि संराशिकरण की धनराशि पेंशन का वह भाग होगी जैसा राज्य सरकार समय-समय पर अपने पेंशनरों के लिए निर्धारित करे ।
11--पेंशन अंशदान के समय में नियमित कर्मचारियों के मूल वेतन का 15 प्रतिशत धन पेंशन निधि में जमा किया जायेगा ।	11--पेंशन अंशदान के समय में नियमित कर्मचारियों के मूल वेतन तथा महंगाई राहत का 15 प्रतिशत धन पेंशन निधि में जमा किया जायेगा ।
20--(2) नगर निगम, आगरा के प्रत्येक कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के उपरान्त नगर निगम की सामान्य निधि से रुपया 251.00 पुरस्कार स्वरूप भुगतान किये जायें ।	20--(2) नगर निगम, आगरा के प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरान्त नगर निगम की सामान्य निधि से 31 अक्तूबर, 1997 से सेवारत निवृत्त के समय रु० 501 पुरस्कार स्वरूप भुगतान किये जायें । 20--(3) नगर निगम, आगरा के वे पेंशनर जो सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य जनपदों में आवासित हो गये हैं और जिन्हें वृद्धावस्था के कारण लम्बी यात्रा में काफी असुविधा होती है उनके मामलों में उनके द्वारा अपने आवासित नगर की भारतीय स्टेट बैंक में पेंशन खाता खुलवाने पर उनकी पेंशन सम्बन्धित बैंक को चेक अथवा ड्राफ्ट द्वारा (ड्राफ्ट की व रजिस्ट्री व्यय की कटौती कर)

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान नियमन	प्रस्तावित संशोधन
	6 माह तक प्रेषित की जा सकेगी परन्तु इन्हें प्रत्येक अप्रैल एवं अक्तूबर माह में स्वयं नगर निगम, आगरा उपस्थित होकर जीवित होने का प्रमाण देना होगा। नगर निगम द्वारा सम्बन्धित बैंक को यह भी सूचित किया जायेगा कि सम्बन्धित पेंशनर के जीवित होने की दशा में ही संप्रेषित पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जाये अन्यथा पेंशन की धनराशि नगर निगम, आगरा को वापस कर दी जाय।

उपरोक्त संशोधन 1 नवम्बर, 1997 से प्रभावी माने जायेंगे। संशोधन का प्रस्ताव नगर निगम के 18वें अधिवेशन की बैठक दिनांक 3 सितम्बर, 1998 में प्रस्ताव संख्या 4 (11) के अन्तर्गत स्वीकृत किया।

ह० (अस्पष्ट),
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, आगरा।

पी० एस० टू० पी०—33 हिन्दी गजट—साप्ता० 8—1999 ई०।
मुद्रक और प्रकाशक—निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

के प्रकाशन की तिथि से 14 दिन के अन्दर प्रस्तुत करे।

दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 ई०

ह० (अस्पष्ट),
कृते जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत।

Shri Ashok Kumar Kamani s/o late Hari Ram Kamani, r/o Siswabazar, Thana Kotibhar, District Mahrajganj (U. P.), one of the partner of the Firm Shri Ganesh Silicate Soda and Glass Factory, Post Siswabazar, District Mahrajganj (U. P.) and its branches, has retired and all its assets and liabilities have been taken over by the continuing partner's. They will be only entitled to realise the dues of the aforesaid Firm from 1.4.99.

54 E

Scanned with OKEN Scanner